दैनिक
लद्दाख टुडे

Title Code: LDHIN00001 | वर्षः 03 अंकः 209 | जम्मू, कश्मीर, लेह, बुधवार 02 सितम्बर 2026 | पृष्ठः 8 | मूल्य 2 रुपए

आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए एससीओ को एकजुट होकर काम करना चाहिए: पीएम मोदी

बिश्केक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम और उसे मिलने वाली फंडिंग को खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने में दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

किर्गिस्तान की राजधानी में एससीओ के सालाना शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में सभी युद्धों और संघर्षों को बातचीत और कूटनीति के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं मिल सकता।

मोदी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी इस बात को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ओर इशारे के तौर पर देखा जा रहा है।

आतंकवाद से निपटने की ज़रूरत पर प्रधानमंत्री की ये बातें इसलिए अहम हैं क्योंकि ये ऐसे समय में कही गई हैं जब नई दिल्ली सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमें आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम और उसे मिलने वाली फंडिंग को खत्म करना होगा

मोदी ने आगे कहा, हमें एक सुर में यह कहना होगा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युद्ध और संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता और उन्हें बातचीत और कूटनीति के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाज़ारों को जोड़ते हैं, व्यापार को आसान बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं।

साथ ही, मोदी ने कहा कि

■ शेष पेज 2...

एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा की समीक्षा की, जेएंडके में मज़बूत आतंकवाद-विरोधी रणनीति की ज़रूरत बताई

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू/श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की और पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक तैयारियों का जायज़ा लिया।

उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आतंकी नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखें और ज़मीनी स्तर पर ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाएं। उन्होंने उभरते खतरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए आक्रामक श्एरिया डोमिनेशनश (इलाके पर नियंत्रण) रणनीति अपनाने को कहा।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए जनता का भरोसा ज़रूरी बताते हुए, उपराज्यपाल ने पुलिस

अधिकारियों को जनता के साथ सीधा संपर्क बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने नागरिकों से बातचीत और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए खास समय तय करने को कहा।

पुलिस स्टेशन स्तर पर कामकाज की समीक्षा करते हुए, उपराज्यपाल ने पारदर्शी, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से शिकायतों के निपटारे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और अधिकारियों को पूरी पेशेवर ईमानदारी के साथ जांच करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने कहा, ष्पुलिस को जनता के साथ मज़बूत और लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। हर जायज़ शिकायत का समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए और हर जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता

■ शेष पेज 2...

जेएंडके में लगभग 2700 करोड़ रूपये के तीन बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में यूनियन टेरिटरी लेवल की हाई-पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी (यूटीएचपीएससी) ने मंगलवार को लगभग 2700 करोड़ रुपये के तीन बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (एचएंडयूडीडी) द्वारा चुने गए इन प्रोजेक्ट्स में जम्मू में तरंग (तवी एरिया रीजेनरेशन एंड ग्रीन ग्रोथ), श्रीनगर में वॉल्ड सिटी और निगीन लेकफ्रंट रिवाइटलाइज़ेशन, और रियासी में कृपा (कटरा रिवाइटलाइज़ेशन इंटीग्रेटेड पिलग्रिमेज एमेनिटीज़) शामिल है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन्हें आधुनिक, टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवंत शहरी जगहें बनाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को मार्केट-लिंक्ड फाइनेंसिंग और प्राइवेट भागीदारी के साथ जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अधिकारी ने कहा, ष्जेएंडके में टिकाऊ और इन्वेस्टमेंट-आधारित शहरी बदलाव को तेज़ी से आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता वाली यूटीएचपीएससी ने भारत सरकार के अर्बन चौलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत कुल 2,692.58 करोड़ रुपये की लागत वाले तीन बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।ष

प्रवक्ता ने कहा कि यह मंजूरी जेएंडके की उन कोशिशों में एक अहम प्रगति है, जिनका मकसद बड़े पैमाने पर विकास के लिए अतिरिक्त संस्थागत, म्युनिसिपल और प्राइवेट कैपिटल जुटाते हुए बदलाव लाने वाले शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूसीएफ फ्रेमवर्क का लाभ उठाना है।

1,567.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले तरंग प्रोजेक्ट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और च्च्-आधारित कमर्शियल विकास के मेल से तवी रिवरफ्रंट और उसके आस-पास के शहरी इलाकों का व्यापक कायाकल्प करने की योजना है।

इस प्रोजेक्ट के फंडिंग स्ट्रक्चर में केंद्र और यूटी सरकार की ओर से 307.05-307.05 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है, जबकि 953.81

■ शेष पेज 2...

संक्षिप्त...

बीजेपी ने मेडिकल इंटर्न की स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग का समर्थन किया, सीएम से निजी दखल की अपील की

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। मंगलवार को बीजेपी की जम्मू-कश्मीर यूनिट ने एमबीबीएस इंटर्न के उस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया, जिसमें वे अपने मासिक स्टाइपेंड में कथित असमानता को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू से अपील की कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से दखल दें और समस्या का समाधान करें।

मेडिकल इंटर्न ने ज़्यादा स्टाइपेंड और काम की बेहतर स्थितियों की मांग को लेकर सोमवार को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। पार्टी के प्रवक्ता डॉ. ताहिर चौधरी ने यहां एक बयान में कहा, ष्बीजेपी हमारे युवा डॉक्टरों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कदम उठाना चाहिए। समान जिम्मेदारी के लिए उचित मुआवजा

■ शेष पेज 2...

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने ज़मीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जेएंडके क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने मंगलवार को कहा कि उसने श्रीनगर के एक निवासी के खिलाफ ज़मीन हड़पने के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (एसएमसी) से बिल्डिंग बनाने की इजाज़त लेने की कोशिश शामिल है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जेएंडके क्राइम ब्रांच की ईओडब्ल्यू कश्मीर ने एफआईआर नंबर 08/2016 के तहत आरपीसी की धाराओं 420/511, 167, 471 और 120-बी के तहत श्रीनगर के सब-जज की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट मुश्ताक अहमद मलिक (पिता गुलाम अहमद मलिक, निवासी बारापाथर, हफ़्त चिनार, श्रीनगर) और तत्कालीन पटवारी (जो अब जीवित नहीं हैं) के खिलाफ दाखिल की गई

■ शेष पेज 2...

कश्मीर के नए आईजी सुजीत कुमार ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। सुजीत कुमार (आईपीएस), जिन्होंने हाल ही में कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (आईजी) का पद संभाला है, ने मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की।

सिविल सचिवालय में हुई इस मुलाकात

■ शेष पेज 2...

जम्मू में दो मल्टी-लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स के लिए 49 करोड़ रूपये से ज्यादा मंज़ूर

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। शहर में ट्रैफ़िक जाम और पार्किंग की समस्या को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 2026-27 के केपेक्स बजट के तहत लगभग 49.34 करोड़ रुपये की लागत वाले दो बड़े मल्टी-लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स को प्रशासनिक मंजूरी दी है।

मंजूर किए गए कामों में परेड में लगभग 24.06 करोड़ रुपये की लागत से एक पार्किंग-सह-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण और एसएमजीएस हॉस्पिटल में 25.27 करोड़ रुपये की लागत से एक मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा का निर्माण शामिल है।

जेएंडके विधानसभा पेपरलेस हुई : एनइवीए पोर्टल के ज़रिए होगा ऑटम सेशन का कामकाज

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया है कि वे 21 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के ऑटम सेशन से पहले अपने सभी विधायी कामकाज को श्नेशनल ई-विधान एप्लीकेशनश (एनइवीए) पोर्टल पर ले जाएं।

कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के तहत, सरकारी बिल, विधायी प्रस्ताव, विधायकों के विधानसभा सवाल और आधिकारिक जवाब अब डिजिटल रूप

से जमा, ट्रैक और प्रोसेस किए जाएंगे ताकि कामकाज पूरी तरह से पेपरलेस हो सके।

इस प्रक्रिया को आसानी से लागू करने के लिए, विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे रोज़ाना अपने अकाउंट्स को चेक करें, खास एनइवीए नोडल अधिकारी नियुक्त करें और सेशन शुरू होने से पहले सभी डिजिटल सबमिशन को वेरिफाई करें।

श्रीनगर में डेली वेजर्स का विरोध प्रदर्शन, तय समय में रेगुलर करने की मांग

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर कैज़ुअल डेली वेजर्स फोरम ने मंगलवार को श्रीनगर में डेली वेजर्स (दिहाड़ी मजदूरों) को रेगुलर करने की प्रक्रिया में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार रेगुलर करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाए और उनकी लंबे समय से

लंबित मांगों को पूरी तरह से हल करने के लिए एक ठोस रोडमैप लागू करे।

चुनाव के समय सरकार द्वारा किए गए वादे को याद करते हुए,

■ शेष पेज 2...

एटीएफ की कीमत 5.46 फीसदी बढ़ी, कमर्शियल एलपीजी का दाम 9.50 रूपये बढ़ा

नई दिल्ली। मंगलवार को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में 5.46 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। वहीं, होटल और रेस्तरां जैसे कमर्शियल जगहों पर इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमत में 19-किग्रा सिलेंडर पर 9.50 रूपये की बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों में हुई वृद्धि के कारण की गई है।

सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल या एटीएफ की कीमत 6.28 रूपये प्रति लीटर

(यानी 5.46 फीसदी) बढ़ाकर 121.28 रूपये प्रति लीटर कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अगस्त को हुई 5 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद हुई है।

इन दो बढ़ोतरी से एयरलाइंस पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उनके कुल ऑपरेटिंग खर्च का 40 फीसदी हिस्सा फीसदी पर ही खर्च होता है।

कमर्शियल एलपीजी की कीमतें 19-किग्रा सिलेंडर के लिए 2,738 रूपये से बढ़कर 2,747.50 रूपये हो गई हैं। 5-किग्रा वाले मार्केट-प्राइस कुकिंग गैस एलपीजी सिलेंडर (जिसे 5-किग्रा एफटीएल कहा जाता है) की कीमत भी 762 रूपये से बढ़ाकर 764 रूपये कर दी गई है।

कीमतों में यह बढ़ोतरी लगातार दो महीनों में हुई कटौती के बाद हुई है - 1 अगस्त को 19-किग्रा सिलेंडर पर 192 रूपये की भारी कटौती और 1 जुलाई को 183.5 रूपये की

■ शेष पेज 2...

सोनिया गांधी की बुक बिलॉन्गिंग पर पेंगुइन का यू-टर्न

प्रकाशक ने इनकार पर बताई पूरी बात, 10 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होनी है किताब

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की लॉन्ग अवेटिड किताब 'बिलॉन्गिंगरू अ जर्नी ऑफ लव' भारत में छपने से पहले ही विवादों में आ गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अब साफ किया है कि किताब के प्रकाशन से पीछे हटने के पीछे किसी तरह का बाहरी या सरकारी दबाव नहीं था। प्रकाशक के मुताबिक, लेखक की टीम और प्रकाशक के बीच एक खास मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी थी।

यह किताब सोनिया गांधी के

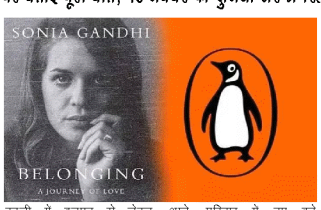

इटली में बचपन से लेकर राजीव गांधी से उनके रिश्ते, नेहरू-गांधी परिवार में उनके आने, परिवार में हुए बड़े व्यक्तिगत दुखों और भारत के साथ उनके रिश्ते की कहानी बताती है। किताब को एक अमेरिकी प्रकाशन हाउस अल्फ्रेड ए नॉफ 10 नवंबर को दुनिया भर में जारी करेगा। हालांकि, भारत में इसे कौन प्रकाशित करेगा, यह अभी साफ नहीं है।

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की प्रवक्ता पल्लवी नारायण ने कहा कि कंपनी इस किताब को प्रकाशित करने के लिए काफी उत्सुक थी। उन्होंने इसे कंपनी का "हार्ड-वॉन एक्विजिशन" बताया था।

प्रकाशक

■ शेष पेज 2...

इल्तिजा मुफ़्ती ने सरकार से प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने को कहा

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ़्ती ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार से प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 12,300 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने को कहा।

इल्तिजा जीएमसी श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे मेडिकल इंटर्न के साथ शामिल हुईं और उनके मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाने की ष्जायज़ मांगष का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, ष्यह बहुत चिंता की बात है कि जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न को देश में सबसे कम स्टाइपेंड में से एक मिल रहा है, जबकि उन पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। इंटर्न को अक्सर 12 से 48 घंटे तक ड्यूटी

■ शेष पेज 2...

------ जम्मू ---------
अधिकतम – 29°C
न्यूनतम – 22°C
------- श्रीनगर -------
अधिकतम – 23°C
न्यूनतम – 19°C

Created by Universal Document Converter

शेष पेज 1 से

बीजेपी ने मेडिकल ...

मिलना चाहिए, और जम्मू–कश्मीर के युवा डॉक्टर सम्मान, न्याय और दूसरे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अपने साथियों के बराबर स्टाइपेंड पाने के हकदार हैं।

आतंकवाद के पूरे ....

कनेक्टिविटी के प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए एससीओ महान सभ्यता, संस्कृति और विचारों का संगम है। मोदी ने बताया कि एससीओ के लिए भारत के विज़न के तीन मुख्य स्तंभ हैं–सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर।

एलजी मनोज सिन्हा ने ...

और ईमानदारी के साथ होनी चाहिए।

उपराज्यपाल ने ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए जम्मू–कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को नार्को–टेरर नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने और उभरते डिजिटल खतरों पर नज़र रखने का निर्देश दिया। साइबर और सोशल मीडिया के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का ज़िक्र करते हुए, उपराज्यपाल ने देश–विरोधी प्रचार, डिजिटल गलत जानकारी और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नज़र रखने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान, डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव ने उपराज्यपाल को जम्मू–कश्मीर में सुरक्षा की कुल स्थिति के बारे में जानकारी दी।आईजीपी, डीआईजी और डिविजनल कमिश्न. रों ने अपने–अपने इलाकों में सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद–विरोधी ऑपरेशन, कानून–व्यवस्था, ड्रग तस्करी और अन्य उभरती चुनौतियों के बारे में उपराज्यपाल को जानकारी दी।

बैठक में कई अन्य अहम मुद्दों पर भी व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने सभी अधिका. रियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र शासित प्रदेश में शांति और कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑपरेशनल सतर्कता बढ़ाएं, एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल रखें और सक्रिय रवैया अपनाएं।

बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू; डीजीपी नलिन प्रभात; गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती; पीएचक्यू में स्पेशल डीजी (समन्वय) एसजेएम गिलानी; उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप के. भंडारी; एडीजीपी (सीआईडी) एम. के. सिन्हा शामिल हुए। सुजीत कुमार, आईजीपी कश्मीर; तेजिंदर सिंह, आईजीपी जम्मू; सारा रिज़वी, आईजीपी, क्राइम ब्रांच; डिविज़नल कमिश्नर; डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

जेएंडके में लगभग ...

करोड़ रुपये मार्केट और पीपीपी फाइनेंसिंग के ज़रिए जुटाने का प्रस्ताव है।

पीपीपी कंपोनेंट के तहत एक हाई–एंड रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक शानदार होटल, एक आधुनिक रिटेल मॉल और उससे जुड़े श्लेफ्ट बैंकश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल और नदी–सुरक्षा के काम भी शामिल हैं, जैसे कि डायाफ्राम वॉल, तटबंध भरना, एंकर स्लैब के साथ रिटेनिंग वॉल और इंटरसेप्टर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। श्वॉल्ड सिटी और निगीन लेकफ्रंट रिवाइटलाइज़ेशनश प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1,010 करोड़ रुपये है। इसका मकसद श्रीनगर के ऐतिहासिक शहरी इलाके को नया रूप देना और शहर के अंदरूनी हिस्सों में झील के किनारे वाले इलाकों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है।

करीब 300 करोड़ रुपये मुख्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐतिहासिक शहर को नया रूप देने पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, पीपीपी (पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत हॉस्पिटैलिटी सेंटर, पोकरीबल लेकफ्रंट और एक प्रीमियम फाइव–स्टार बुटीक होटल बनाया जाएगा।

रियासी में 113.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले कृपा प्रोजेक्ट का फोकस कटरा में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं, आवाजाही के मैनेजमेंट और संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर होगा।

इसका एक अहम हिस्सा श्कटरा गेटवे सेंटरश है। इसे आधे एकड़ ज़मीन पर सात (5+2) मंज़िला मिक्स्ड–यूज़ सुविधा के तौर पर बनाने की योजना है, जिसका बिल्ट–अप एरिया 1.39 लाख वर्ग फुट होगा। इसमें तीर्थयात्रियों के लिए 36 डॉरमेट्री में 480 बेड, 35 गेस्ट रूम, रिटेल आउटलेट, कम्युनिटी डाइनिंग हॉल और प्रार्थना के लिए खास जगहें होंगी।

पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में मल्टी–लेवल कार पार्किंग सुविधा, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्रा पर्ची काउंटर के पास बस के लिए खास जगह (बस बे) बनाने का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट में संस्थागत ढांचे को नया रूप देने के लिए 15.25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें आधुनिक कमर्शियल ऑफिस स्पेस, रिटेल कियोस्क और कटरा म्युनिसिपल कमेटी के लिए बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं शामिल हैं।

कश्मीर के नए आईजी ...

के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारी को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

बाद में, मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी।

श्रीनगर में डेली वेजर्स ...

फोरम के अध्यक्ष सज्जाद अहमद पर्रे ने कहा कि अब सत्ताधारी सरकार के लिए डेली वेजर्स के मुद्दों जिसमें रेगुलर करना और पेंशन बहाल करना शामिल है पर ध्यान देना ज़रूरी है।

उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स को रेगुलर करने का रोडमैप तैयार करने के लिए जेके विधानसभा में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी समय–सीमा छह महीने तय की गई थी, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बावजूद कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।

पर्रे ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। उन्होंने कहा, ष्न तो हमारे खर्चों का भुगतान किया गया है, न ही हमारी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, और न ही कोई स्थायी नीति लाई गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के समय सरकार के वादों के आधार पर लगभग चार लाख डेली वेजर्स और कैजुअल वर्करों के साथ–साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सरकार का समर्थन किया था।

उन्होंने कहा, ष्लेकिन आज, सरकार उन्हें भूल गई है और अपने वादे तोड़ दिए हैं।ß

नेता ने डेली वेजर्स, कैजुअल मजदूरों, एसपीओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दुर्दशा को दूर करने में सरकार की विफलता की भी आलोचना की, जबकि विधायक ज़्यादा वेतन ले रहे थे। उन्होंने कहा, ष्हमारे कर्मचारी परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है।

कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के वादे के साथ चुनाव प्रचार करने वाले विधायकों से अपील करते हुए, उन्होंने डेली वेजर्स के मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को अगले विधानसभा, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय और संसदीय चुनावों के दौरान एक बार फिर जनता का समर्थन मांगना होगा।

एटीएफ की कीमत 5.46 ...

कटौती। 1 जुलाई और 1 अगस्त को कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में ये दो कटौतियां, जून में वेस्ट एशिया संकट के कारण कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद की गई थीं।

फरवरी के आखिर में संघर्ष शुरू होने के बाद, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 19–किग्रा सिलेंडर पर 1,373 रूपये की भारी बढ़ोतरी हुई थी –– फरवरी में 1,740.50 रूपये से बढ़कर जून में 3,113.50 रूपये हो गई थी।

एटीएफ और एलपीजी की कीमतें – जिन्हें हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर बदला जाता है – अलग–अलग राज्यों में वैट जैसे स्थानीय टैक्स के आधार पर अलग–अलग होती हैं।

घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमतें 14.2–किग्रा सिलेंडर के लिए 942 रूपये पर ही बनी हुई हैं। घरेलू एलपीजी की कीमतें आखिरी बार 7 जून को 14.2–किलो वाले सिलेंडर पर 29 रुपये बढ़ाई गई थीं। मार्च में वेस्ट एशिया संकट की वजह से सप्लाई में रुकावट और इंटरनेशनल एनर्जी की कीमतों में उछाल के बाद दाम 60 रुपये बढ़ गए थे।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, जिन्हें मई में प्रति लीटर लगभग 7.50 रुपये बढ़ाया गया था।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने ...

है।

उन्होंने कहा कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने आपस में मिलीभगत करके खसरा नंबर 642 वाली ज़मीन हड़पने और जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके एसएमसी से बिल्डिंग बनाने की इजाज़त लेने की कोशिश की थी।

इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और जांच के दौरान आरोप सही पाए गए। जांच में धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़, ज़रूरी तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग का पता चला। जांच को ष्साबितß मानते हुए बंद कर दिया गया और न्यायिक फैसले के लिए सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

प्रवक्ता ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने लोगों को सलाह दी है कि वे इस तरह की आर्थिक धोखाधड़ी से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना एसएसपी, ईओडब्ल्यू कश्मीर को दें।

सोनिया गांधी की बुक ...

के मुताबिक, लिखित सामग्री सामान्य संपादकीय प्रक्रिया से गुजरी। इस दौरान कई मुद्दों पर लेखक की टीम के साथ चर्चा हुई।

कुछ बदलावों पर सोनिया गांधी की टीम सहमत हुई, जबकि कुछ मामलों में प्रकाशक ने उनकी बात स्वीकार की।

लेकिन अंत में "एक खास मुद्दे" पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद लेखक की टीम ने आगे प्रकाशन नहीं करने की इच्छा जताई। अब वो खास मुद्दा क्या था क्या नहीं इस पर अभी पेंगुइन ने उस खास मुद्दे का खुलासा नहीं किया है। उसका कहना है कि सोनिया गांधी के साथ हुए समझौते और लेखक की गोपनीयता के कारण वह बातचीत की जानकारी साझा नहीं कर सकता।

हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लिखित सामग्री के कुछ हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और चीन से जुड़े मुद्दों पर संपादन को लेकर चर्चा हुई थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसी आधार पर सरकारी दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए हैं।

पेंगुइन ने इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि फैक्ट चेक और लेखकों को संपादन से जुड़े सुझाव देना प्रकाशन प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। उसके अनुसार, किताब को प्रकाशित करने की इच्छा बातचीत के दौरान बनी हुई थी।

इल्तिजा मुफ़्ती ने सरकार ...

करनी पड़ती है और पूरे जेएंडके में उन्हें अक्सर बुनियादी छुट्टियां और पर्याप्त अवकाश भी नहीं मिलता है।ß

उन्होंने सरकार से प्रदर्शन कर रहे इंटर्न के साथ तुरंत सार्थक बातचीत शुरू करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और बिना किसी देरी के उनका स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटर्न को उनके द्वारा दी जाने वाली कठिन सेवाओं के अनुरूप काम करने की उचित स्थितियां, पर्याप्त छुट्टियां और बुनियादी सुरक्षा मिले।

इल्तिजा ने आगे कहा, ष्30,000 रुपये के स्टाइपेंड की मांग उचित और जायज़ है। कई राज्यों ने पहले ही अपने इंटर्नशिप स्टाइपेंड में काफी बढ़ोतरी की है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल लगभग 45,000 रुपये देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश ने अपना स्टाइपेंड 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है, और बिहार ने भी इसमें संशोधन किया है।

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले युवा डॉक्टरों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे देश में सबसे कम वेतन पाने वाले मेडिकल इंटर्न होने के बावजूद बिना पर्याप्त छुट्टियों या सुविधाओं के 12 से 48 घंटे की शिफ्ट में काम करें। उनकी मांग जायज़ है, और सरकार को तत्परता और संवेदनशीलता के साथ इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

पीडीपी नेता ने आगे कहा, ष्सरकार को अपनी प्राथमिकताओं पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे समय में जब सरकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों पर भारी सार्वजनिक संसाधन खर्च किए जाते हैं, उन युवा डॉक्टरों को मामूली और जायज़ बढ़ोतरी देने से इनकार करना उचित नहीं ठहराया जा सकता, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं।

HELP LINE

IMPORTANT CONTACT NUMBERS – UT LADAKH

POLICE DEPARTMENT (SPs)

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	EMAIL
1	SP Leh	Shree Raam R (IPS)	8899222100	01982-244031	ssp-leh1@police.ladakh.gov.in
2	SP Nubra	Sh. Stanzin Losal (JKPS)	9419037139 8825045363	–	spnubra@gmail.com (Temporary)
3	SP Changthang	Sh. Syed Zaheer Abass (JKPS)	9797995888	7006368375	sp-changthang@police.ladakh.gov.in
4	SP Sham	Sh. Aijaz Malik (JKPS)	9419923000	6006424325	sp-sham@police.ladakh.gov.in
5	SP Kargil	Sh. Niten Yadav (IPS)	9999339994	01985-232645/232704	sspkargil@police.ladakh.gov.in Fax No. 232645
6	SP Drass	Sh. Istiqaq A. Kacho (JKPS)	8492097235	–	sp-drass@police.ladakh.gov.in
7	SP Zanskar	Sh. Rigzen Sangdup	9419287779 6006164711	–	sp-zanskar@police.ladakh.gov.in

DEPUTY COMMISSIONERS

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	PA TO DC / EMAIL
1	DC Leh	Sh. Romil Singh Donk (IAS)	7982319218	01982-252685	Stanzin – 8494072166
2	DC Kargil	Sh. Rakesh Kumar (IAS)	8604286353	01985-232216	Skarma Gurmat – 9622254259
3	DC Changthang	Sh. Nitish Rajora (IAS)	7053991969	(Temporary)	PA to DC – Kunzes Dolma 6005297553
4	DC Nubra	Sh. Mukul Beniwal (IAS)	8800308665	01982-252049	–
5	DC Zanskar	Sh. Omkar Rajendra Gundage (IAS)	8668894331	–	dc-zanskar@ladakh.gov.in
6	DC Sham	Smt. Kunzes Angmo	9419179108	–	–
7	DC Drass	Sh. Imteeaz Kacho (JKAS)	–	–	–

These numbers are for public assistance and urgent communication only.

FOR ANY EMERGENCY, DIAL 112

Created by Universal Document Converter

दया, प्रेम, सेवा और करुणा धर्म के मुख्य गुण है। धर्म के बिना धन और काम दिशाहीन हो सकते हैंरू संत सुभाष शास्त्री

उधमपुर, 01 सितम्बर (संजीव शर्मा)। चनैनी के गीता भवन में जारी श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को दूसरे दिन युग पुरुष आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के शिष्य संत सुभाष शास्त्री ने संगत को बताया कि जगत में चार पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव जीवन में इन्हें अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले के और आज के लोगों में बड़ा अंतर है। पहले के बुद्धिमान मनुष्य धर्म और मोक्ष के लिए प्राण न्योछावर करते थे अर्थात कठिन तप आदि करते थे। अर्थ – (धन) धर्मपूर्वक परिश्रम से ही अर्थोपार्जन करते थे। वे धन से आवश्यकताओं की पूर्ति और धर्म कमाते थे। काम–वासना को प्रारब्ध पर छोड़ देते थे। संत सुभाष शास्त्री ने कहा कि अब जमाने की गति उल्टी हो गई है। आज लोग अर्थ और काम के लिए दिन–रात खून पसीना एक करते हैं और धर्म और मोक्ष को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं।

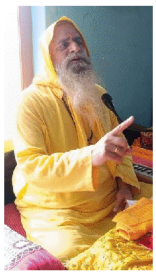

धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग–विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग–विलास का फल इन्द्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन–निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है।

शास्त्री जी ने दोहराया कि धर्म मनुष्य के जीवन का आधार है। यह हमें सत्य, न्याय और सदाचार का मार्ग दिखाता है। दया, प्रेम, सेवा और करुणा धर्म के मुख्य गुण है। धर्म के बिना धन और काम दिशाहीन हो सकते हैं।

अर्थ–अनुचित तरीके से कमाया गया धन सुख नहीं देता। धन साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं।

काम–काम की पूर्ति धर्म और मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को अशांत कर सकती हैं।

मोक्ष का अर्थ है जन्म–मरण के बंधन से मुक्ति। चार पुरुषार्थों में इसे जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। यह आत्मज्ञान और परम सत्य की अनुमति से प्राप्त होता है।

प्रशासनिक टीम ने तहसीलदार की अध्यक्षता में पतंगों वाली दुकानों की कि जांच

चाइनीज व कांच से कोटिड धागों को किया गया जब्त

दुकानदारों को गट्टू डोर व कांच कोटिड डोर न बेचने की कि अपील

उधमपुर, 01 सितम्बर (संजीव शर्मा)। जन्माष्टमी के त्योहार पर ऊधमपुर जिला में खूब पतंगबाजी होती है और इस पतंगबाजी में चाइनीज धागा व कांच से कोटिड धागे का इस्तेमाल होता है जो कि आम लोगों के लिए खतरा है। कई लोग इससे जख्मी हो जाते हैं या फिर कई लोगों की जान तक भी चली जाती है।

इसी के चलते मंगलवार को उधमपुर जिला प्रशासन द्वारा एक टीम का गठन तहस. ीलदार उधमपुर की अध्यक्षता में किया गया, जिन द्वारा पतंग व धागा बेचने वाली दुकानों पर जाकर जांच की गई की गई कि कोई चाइनीज धागा या फिर कांच से कोटेड धागा तो नहीं बेच रहा। कई दुकानों से कांच से इस्तेमाल पतंगबाजी में ना

कोटेड धागा जब्त भी किया गया। इस दौरान दुकानदारा. ें को साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि वह कांच से कोटेड धागा व चाइनीज धागा ना बेचें। साथ–साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वह इन धागों का करें ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंच सके।

तहसीलदार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल रोड़ पर तेज रफ्तार वैन ने बढ़ाई जाम की समस्या

स्कूल बस और विद्यार्थी काफी देर तक फंसें

कटरा (रोहित शर्मा)। कटरा के अस्पताल रोड़ पर खराब खस्ता हालत यातायात व्यवस्था के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी बीच आज एक अजीबा. ेगरीब घटना सामने आई, जब पहले से लगे भारी ट्रैफिक के दौरान एक मारुति वैन चालक की जल्दबाजी ने जाम की स्थिति को और गंभीर बना दिया।जानकारी के अनुसार, स्कूल की छुट्टी के समय अस्पताल रोड़ पर पहले से ही वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। इसी दौरान एक मारुति वैन चालक तेज रफ्तार से आया और आगे निकलने के प्रयास में अन्य वाहनों को ओवरटेक करने लगा। बताया जा रहा है कि चालक की इस हरकत के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई और जाम की स्थिति काफी देर तक बनी रही।जाम के कारण एक स्कूल बस भी सड़क पर फंस गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठे हुए थे। गर्मी और लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के कारण बच्चे परेशान नजर आए। बताया जा रहा है कि जाम की स्थिति के चलते आसपास के लोगों और अन्य वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।स्थानीय लोगों ने जब वैन चालक को समझाने और

यातायात व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की तो आरोप है कि चालक ने उनके साथ भी बदसलूकी शुरू कर दी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखा गया।

अस्पताल रोड़ पर आए दिन लगने वाले जाम को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन और यातायात विभाग से उचित कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि स्कूल की छुट्टी के समय और व्यस्त घंटों के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों, मरीजों और आम लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।

सैनिक स्कूल नगरोटा में आल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स-2026 की शुरूआत

जम्मू। आल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स 2026 (ग्रुप 'ए') की शुरूआत आज सैनिक स्कूल नगरोटा में हुई। इसमें आठ सैनिक स्कूलों और उनसे जुड़े संस्थानों के युवा खिलाड़ी छह दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता, आपसी भाईचारे और खेल कौशल के प्रदर्शन के लिए एक साथ आए है।

मुख्यालय व्हाइट नाइट कार्प्स के चीफ आफ स्टाफ और लोकल बोर्ड आफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर ने मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह की शुरूआत एक शानदार मार्च पास्ट के साथ हुई जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने अनुशासन, निष्पक्षता, ईमानदारी और खेल भावना को बनाए रखने का संकल्प लिया।

युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर ने इस बात पर जोर दिया कि खेल आत्मविश्वास से भरे, अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने टीम वर्क, नेतृत्व, दृढ़ता और

प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का आनंद लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। सैनिक स्कूल नगरोटा के प्रिंसिपल, कैप्टन शिबू देवासिया ने भाग लेने वाली टीमों, अधिकारियों और मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने नेशनल गेम्स की मेजबानी करने के सम्मान के लिए आभार और गर्व व्यक्त किया और सभी प्रतिभागियों को भरोसा दिलाया कि स्कूल हर दल के लिए एक अच्छी तरह से आयोजित, ज्ञानवर्धक और यादगार अनुभव प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन खेलों में सैनिक स्कूल नगरोटा, सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, श्रीमती केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल लोहार माजरा कुरुक्षेत्र, वुड्स पार्क स्कूल हमीरपुर, रायल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल फतेहाबाद और दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा की टीमें हिस्सा ले रही हैं।

प्रतिभागी सब–जूनियर और जूनियर आयु वर्गो में लड़कों और लड़कियों की श्रेणियों में बास्केटबाल, वालीबाल, एथलेटिक्स, डिबेट और क्विज में मुकाबला करेंगे। प्रतियोगिता के अलावा, नेशनल गेम्स का उद्देश्य युवा कैडेटों को अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क, आत्मविश्वास और मजबूती विक. सित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये ऐसे मूल्य हैं जो सैनिक स्कूल प्रणाली के मूल में है। यह चैंपियनशिप 05 सितंबर 2026 को खत्म होगी जिसमें टीमें प्रतिष्ठित चैंपियनशिप सम्मान के लिए मुकाबला करेंगी।

इस्कॉन मंदिर की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आज निकाली जाएगी शोभायात्रा

उधमपुर, 01 सितम्बर (संजीव शर्मा)। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर इस्कॉन मंदिर उधमपुर की ओर से 02 सितम्बर 2026 बुधवार को सुबह 09 बजे से अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा तथा सांय 04 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह शोभायात्रा इस्कॉन मंदिर से प्रारंभ होगी तथा विभिन्न बाजारों से होती हुई वापस मंदिर में पहुंचकर समाप्त होगी। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कई झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी।

वहीं 04 सितम्बर 2026 शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर इस्कॉन मंदिर में शाम 07 बजे गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा गौरां आरती की जाएगी तथा भजन संध्या एवं नव योगेंद्र स्वामी जी महाराज द्वारा महा अभिषेक, 108 प्रकार भोग व महा आरती की जाएगी तथा प्रसाद वितरित किया जाएगा।

यह कैसा विकास, बनने से पहले ही टूटा नाला

करण अत्री ने लिया जायजा, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी से मांगी जवाबदेही

रामगढ़। विधानसभा रामगढ़ में विकास इसकदर हो रहा है कि बनने से पहले ही निर्माणकार्य टूट रहे है। रामगढ़ बाजार में चौक से पहले पानी की निकासी के लिए करोड़ो की लागत से बन रहे नाले का एक

हिस्सा ढहने की सूचना मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता करण अत्री ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद अत्री अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और संबंधित ठेकेदार व पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर नाला ढहने के कारणों को लेकर जवाब मांगा। मौके पर मौजूद ठेकेदार अरुण शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण नाले के निर्माण में तैयार किए गए बेस को पर्याप्त मजबूती नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि बेस को पूरी तरह पक्का होने में करीब 28 दिन का समय लगता है, लेकिन बारिश के चलते मजबूती नहीं आने के कारण नाले का संबंधित हिस्सा ढह गया। करण अत्री ने ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने दो साल की गारंटी की जिम्मेदारी लेते हुए आश्वासन दिया है कि भविष्य में काम में किसी प्रकार की दिक्कत आने पर वह इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। विभाग से भी इसी तरह का आश्वासन लिया गया है। अत्री ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रामगढ़ के लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस काम पर खर्च किए जा रहे 9 करोड़ रुपये का पाई–पाई का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि यह जनता का पैसा है। अत्री ने मौजूदा भाजपा विधायक डॉ. देवेंद्र कुमार मनयाल की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेंडर के तहत कराया जा रहा निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।

जिंदडलैहड मोड नहर पर बनी पुली का विधायक ने किया उद्घाटन

मार्ग पर आवाजाही शुरू होने पर लोगों ने ली राहत की सांस

आरएस पुरा। आरएस पुरा–चक इस्लाम मुख्य सड़क

पर गांव जिंदडलैहड मोड के पास नहर पर बन रही पुली का निर्माण कार्य पूरा विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने पुली का उद्घाटन किया और मार्ग को राहगीरों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वही मार्ग खुलने से क्षेत्र के लोगों ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि पुली के निर्माण कार्य के चलते मार्ग पिछले के महीना से बंद पड़ा हुआ था। इस मौके पर विधायक ने पुली का उद्घाटन तथा निरीक्षण करने के बाद कहा कि आरएस पुरा–चक इस्लाम मुख्य सड़क पर वहां पडते जिंदडलैहड मोड नहर पर बनी पुली टूट जाने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जिसके चलते इस कार्य को बीते महीने शुरू करवाया गया था और आज कार्य पूरा होने पर सड़क को राहगीरों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर दर्जनों पंचायत के लोग निर्भर करते हैं और यही मार्ग दो विधानसभा क्षेत्र को भी जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत इस कार्य को लगभग 13 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया है और उनका प्रयास रहेगा कि जहां पर भी सड़कों एवं पुलों की हालत खस्ता हो चुकी है उनकी हालत को सुधारने के लिए उनकी तरफ से राशि मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण क्षेत्र में कुछ सड़कों की हालत काफी खराब हुई है जिसका मरम्मत कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के अधिकारी राजेंद्र कुमार, भाजपा के मंडल अध्यक्ष देवी दिता नीटा, मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह चौहान, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह राजू, पूर्व पंच दर्शन सिंह लाडी, गार सिंह, नंबरदार शालू राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

जम्मू–कश्मीर में सजेगा विश्व सिनेमा का भव्य मंच

पहला जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफ जेके 2026) 07 से 10 सितम्बर तक

'रंग–ए–सिनेमा' के रंगों में रंगेगा श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू

उधमपुर, 01 सितम्बर (संजीव शर्मा)। जम्मू–कश्मीर के सांस्कृतिक और रचनात्मक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रदेश पहली बार जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफ जेके 2026) की मेजबानी करने जा रहा है। 'रंग–ए–सिनेमा' थीम पर आधारित यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 07 से 10 सितम्बर 2026 तक श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में आयोजित किया जाएगा।

यह महोत्सव जम्मू–कश्मीर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, कला, विरासत और रचनात्मक प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस आयोजन के माध्यम से जम्मू–कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, संस्कृति और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

50 देशों से 1,100 से अधिक प्रविष्टियां

आईएफएफजेके 2026 को दुनिया भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। महोत्सव के लिए लगभग 50 देशों से 1,100 से अधिक फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 41 देशों की 135 फिल्मों का चयन किया गया है।

यह अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि जम्मू–कश्मीर की धरती अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, सिनेमा और रचनात्मकता के वैश्विक मंच के रूप में भी अपनी नई पहचान बना रही है।

सिनेमा के साथ विकास और पर्यटन को मिलेगी नई दिशा

जम्मू–कश्मीर सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से आयोजित यह महोत्सव केवल फिल्मों की स्क्रीनिंग तक सीमित नहीं है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन प्रदेश में पर्यटन, रोजगार, होटल एवं हॉस्पिटैलिटी, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और रचनात्मक उद्योगों के विकास के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

देश–विदेश से आने वाले फिल्मकारों, कलाकारों और सिनेमा प्रेमियों को जम्मू–कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता को करीब से जानने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल सकती है।

कश्मीर के साथ जम्मू में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं

इस अवसर पर डॉ. प्रदीप कुमार महाजन (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी) चेयरमैन एनआईएमएस उधमपुर (जेएंडके) ने कहा कि जम्मू–कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को कश्मीर के साथ–साथ जम्मू संभाग में भी समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि जम्मू केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है। जम्मू संभाग में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और सांस्कृतिक विविधता की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि उधमपुर, रामनगर, पटनीटॉप, नत्थाटॉप, मानसर, सुरईसर, सुद्धमहादेव, शिवखोड़ी, भद्रवाह और किश्तवाड़ जैसे क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर और अधिक प्रमुखता से स्थापित किया जा सकता है।

'कश्मीर की खूबसूरती दुनिया जानती है, अब जम्मू की अनदेखी खूबसूरती को भी विश्व के सामने लाने का समय है।'

डॉ. महाजन ने कहा कि आईएफएफजेके 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जम्मू संभाग की पर्यटन संभावनाओं को दुनिया तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। जब देश–विदेश के फिल्मकार और कलाकार जम्मू की खूबसूरत वादियों, पहाड़ों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक विरासत और स्थानीय संस्कृति को देखेंगे, तो भविष्य में यहां फिल्म शूटिंग, पर्यटन और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरए होटल एवं पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा तथा स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को नए बाजार मिल सकते हैं।

यह केवल फिल्म फेस्टिवल नहीं, विकास की नई शुरुआत है।

डॉ. महाजन ने कहा कि जम्मू–कश्मीर में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होना प्रदेश के विकास की दिशा में एक नई और सकारात्मक शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर की वादियां केवल खूबसूरत दृश्य नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का खजाना हैं। जब इन कहानियों को विश्व सिनेमा का मंच मिलेगा, तो प्रदेश के पर्यटन, रोजगार, संस्कृति और युवा प्रतिभाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है उन्हें अवसर, मंच और वैश्विक पहचान प्रदान करने की। आईएफएफजेके 2026 स्थानीय कलाकारों और युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मक समुदाय से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है।

डॉ. महाजन ने उम्मीद व्यक्त की कि आईएफएफजेके 2026 की सफलता के बाद जम्मू–कश्मीर में भविष्य में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, सांस्कृतिक, खेल और पर्यटन आयोजनों का मार्ग प्रशस्त होगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों की अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति और संभावनाएं हैं तथा संतुलित, समावेशी और सतत पर्यटन विकास से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है।

विश्व सिनेमा से विश्व पर्यटन तक

उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर को आने वाले समय में फिल्म, पर्यटन, संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के वैश्विक केंद्र के रूप में विक. सित करने की दिशा में सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।

आईएफएफजेके 2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। जहां सिनेमा केवल कहानियां दिखाएगा ही नहीं, बल्कि जम्मू–कश्मीर की सुंदरता, संस्कृति और विकास की संभावनाओं की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा।

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

बांग्लादेश टेस्ट

तारिक रहमान की मेजबानी करने की भारत की उत्सुकता सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार से कहीं ज्यादा है। यह एक कठोर सच्चाई को दिखाता हैरु नई दिल्ली ने ढाका में वह रणनीतिक पकड़ खो दी है जो उसे कभी हासिल थी, और अब वह बिना उन राजनीतिक हालात के अपना प्रभाव फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, जिनकी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ उसके रिश्ते इतने सहज थे। दिल्ली में यह सोच सकती है कि रहमान की यात्रा एक रीसेट बटन की तरह काम करेगी। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश बदल गया है, उसकी राजनीति बदल गई है, और भारत से उसकी उम्मीदें भी बदल गई हैं।

किसी भी मजबूत रिश्ते के लिए नई शर्तों पर बातचीत करनी होगी। भारत में हसीना की मौजूदगी एक तात्कालिक बाधा है। उनके प्रत्यर्पण की ढाका की मांग सिर्फ एक कानूनी अनुरोध नहीं है। यह इस बात की परीक्षा बन गई है कि क्या भारत उनके हटने के बाद हुए राजनीतिक बदलाव को स्वीकार करता है। भारतीय धरती से बांग्लादेश को संबोधित करने के उनके फैसले ने समस्या को और मुश्किल बना दिया है। दिल्ली का कानूनी रुख चाहे जो भी हो, ढाका अपने पूर्व नेता की लगातार मौजूदगी और सार्वजनिक गतिविधियों को इस बात के सबूत के तौर पर देख सकता है कि भारत ने नई राजनीतिक सच्चाई के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठाया है।

इससे रहमान के लिए एक दुविधा पैदा होती है। दिल्ली का दौरा करना बांग्लादेश के हित में है। भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब व्यापार, ऊर्जा, पानी, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच जैसे मुद्दे शामिल हों। लेकिन रहमान भारत पर निर्भर नहीं दिख सकते, खासकर तब जब उन्होंने ऐसे राजनीतिक माहौल में सत्ता हासिल की हो जो दिल्ली के साथ हसीना की लंबी साझेदारी से उपजे असंतोष से बना हो। इसलिए भारत को यह समझने की जरूरत है कि पुराने समझौते को बस ऐसे ही बहाल नहीं किया जा सकता। हसीना के दौर में सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ क्योंकि दोनों सरकारों को करीबी तालमेल में रणनीतिक फायदा दिखता था।

लेकिन उस तालमेल ने बांग्लादेश में यह धारणा भी पैदा की कि भारत एक दोस्ताना सरकार के लिए लोकतांत्रिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करने को तैयार था। भरोसा फिर से बनाने के लिए केवल औपचारिक सम्मान से ज्यादा कुछ करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान का पहलू दांव को और ऊँचा कर देता है। इस्लामाबाद के साथ बांग्लादेश का नया सैन्य और कूटनीतिक जुड़ाव इस बात की याद दिलाता है कि ढाका के पास अब अपने रिश्तों में विविधता लाने के ज्यादा मौके हैं। भारत को पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के हर जुड़ाव को रणनीतिक खतरे के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह यह नहीं मान सकता कि सिर्फ भूगोल ही भारत की प्रधानता की गारंटी देगा।

इसका जवाब ढाका से वफादारी की मांग करना नहीं है। इसका जवाब भारत के साथ साझेदारी को साफ तौर पर फायदेमंद बनाना है। इसका मतलब है बांग्लादेश को एक संप्रभु पड़ोसी के तौर पर देखना, जिसके हित कभी-कभी भारत से अलग हो सकते हैं, और साथ ही सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सीमा पर भारत की अपनी मुख्य चिंताओं की रक्षा करना। इसका मतलब यह भी है कि लंबे समय के आपसी हितों को हसीना के अनसुलझे भविष्य से अलग करके देखा जाए। प्रत्यर्पण (म.जतंकपजपवद) एक मुश्किल कानूनी और राजनीतिक मुद्दा हो सकता हैय लेकिन व्यापक रिश्ते हमेशा इसी पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए, अगर रहमान का दौरा होता है, तो उसे उनके स्वागत की भव्यता से नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली घटनाओं से आंका जाना चाहिए। क्या दोनों सरकारें पुराने राजनीतिक गठबंधनों के बजाय आपसी सहयोग और बराबरी पर आधारित रिश्ते बना सकती हैं? भारत के लिए यही असली परीक्षा है। मकसद हसीना के दौर वाले बांग्लादेश को वापस पाना नहीं होना चाहिए। बल्कि मकसद उस बांग्लादेश के साथ रिश्ते बनाना होना चाहिए जो अभी मौजूद है।

मोहन भागवत की अमेरिका यात्राः भारतीय चिंतन की सार्थक प्रस्तुति

ललित गर्ग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की अगस्त 2026 की अमेरिका यात्रा को केवल प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम तक सीमित करके देखना उसके व्यापक अर्थ को छोटा करना होगा। न्यूयार्क में 29 अगस्त को आयोजित 'एक विश्व, एक मानवता' कार्यक्रम में उनका संबोधन ऐसे समय हुआ, जब संघ को लेकर भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेक धारणाएं, आरोप और पूर्वाग्रह सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे वातावरण में भागवत ने जिस प्रकार विविधता, संवाद, सेवा, सह-अस्तित्व और मानवीय एकात्मता को केंद्र में रखा, उसने संघ की विचारधारा को उसके समर्थकों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक समाज के सामने भी एक अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया। यह यात्रा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसके विचार अब भारत की सीमाओं से बाहर भी व्यापक चर्चा का विषय बन रहे हैं। भागवत का अमेरिका जाना वस्तुतः संघ के विचार को प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से समझाने का अवसर बना। संघ के बारे में भारत में लंबे समय से दो विपरीत धारणाएं दिखाई देती रही हैं। एक पक्ष उसे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभावना, सेवा और सामाजिक संगठन की विराट शक्ति मानता है, जबकि दूसरा पक्ष उसके विचारों को संकीर्ण धार्मिक राजनीति से जोड़कर देखता है। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने समय-समय पर संघ और उसके विचारों पर गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाए हैं। अमेरिका में भी कार्यक्रम से पहले कुछ संगठनों और राजनीतिक व्यक्तियों ने भागवत की यात्रा और संघ की विचारधारा पर आपत्तियां व्यक्त कीं। ऐसे माहौल में किसी संस्था की वास्तविक छवि केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं बनती, वह संवाद से बनती है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है। भागवत ने अपने विचार विरोधियों पर आक्रमण करके नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन की व्याख्या करके सामने रखे। इससे संघ को लेकर बनी धारणाओं पर बहस का एक नया आधार तैयार हुआ।

न्यूयार्क में भागवत के वक्तव्य का सबसे अधिक चर्चित पक्ष उनका हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर स्पष्ट कथन रहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता। यह कथन राजनीतिक नारे से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें हिंदुत्व की उनकी व्याख्या को सामाजिक समावेश के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सत्य एक है और उसे समझने तथा व्यक्त करने के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं। भारतीय परंपरा की यही विशेषता है कि वह मतभिन्नता को अस्तित्व के संकट के रूप में नहीं, बल्कि सत्य की विविध अभिव्यक्तियों के रूप में देखने की क्षमता रखती है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है-यदि हिंदुत्व का अर्थ भारत की सांस्कृतिक चेतना है, तो क्या वह किसी समुदाय को भारत से बाहर कर सकता है? भागवत का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिखाई देता है। उनका कथन हिंदुत्व की उस व्याख्या को सामने रखता है, जिसमें भारतीयता किसी एक पूजा-पद्धति की बपौती नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासत है।

भागवत ने अमेरिका में भारत की विविधता को उसकी कमजोरी नहीं, शक्ति बताया। उनके अनुसार विविधता और एकता भारत के स्वभाव में ही अंतर्निहित है। भारत में भाषा, जाति, पंथ, पूजा-पद्धति और परंपराओं की असंख्य धाराएं हैं, फिर भी इन्हें एक साझा सभ्यतागत चेतना जोड़ती रही है। यह संदेश आज के विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अनेक देशों में धार्मिक पहचान, नस्लीय भेद, सांस्कृतिक असहमति और राजनीतिक ध्रुवीकरण सामाजिक तनाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय भारत का अनुभव यह बताता है कि भिन्नताओं को मिटाना आवश्यक नहीं, उन्हें सम्मान देकर भी एकता स्थापित की जा सकती है। यही विचार भागवत के संबोधन को सामान्य राजनीतिक भाषण से ऊपर उठाता है। उनका आग्रह था कि विविधता को स्वीकार ही नहीं, सम्मान और संरक्षण भी मिलना चाहिए।

संघ की सार्वजनिक छवि का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक विमर्श से निर्मित हुआ है, जबकि संघ स्वयं को सामाजिक संगठन और सेवा-आधारित सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। भागवत ने अमेरिका में भी सेवा, सामाजिक समरसता और संवाद को परिवर्तन का आधार बताया। यही वह बिंदु है जहां संघ की छवि को केवल चुनावी राजनीति के चश्मे से देखने की सीमा सामने आती है। किसी संगठन को समझने के लिए उसके राजनीतिक प्रभाव के साथ उसकी सामाजिक गतिविधियों, सेवा-कार्य, संगठनात्मक संस्कृति और वैचारिक आधार को भी देखना आवश्यक है। भागवत की यात्रा ने कम से कम इतना अवसर अवश्य दिया कि संघ को उसके अपने शब्दों और उसके सरसंघचालक की प्रत्यक्ष व्याख्या के आधार पर सुना जाए।

अमेरिका में बसे भारतीयों से भागवत ने एक संतुलित संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश में वे रह रहे है, वह उनकी कर्मभूमि है और वहां के प्रति उनकी निष्ठा तथा दायित्व सर्वोपरि है। साथ ही भारत उनकी जन्मभूमि है, जिससे उन्हें मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक संस्कारों की विरासत मिली है। यह दृष्टि प्रवासी भारतीयों के सामने पहचान के संघर्ष के बजाय पहचान के समन्वय का मार्ग रखती है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना और जिस समाज में रह रहे हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखना-दोनों एक साथ संभव है। यही भारतीय संस्कृति की उदारता है। यह भी तथ्य है कि भागवत के कार्यक्रम का अमेरिका में विरोध हुआ और संघ की विचारधारा को लेकर तीखी आलोचनाएं सामने आईं। लेकिन लोकतांत्रिक समाज में किसी विचार का उत्तर उसे दबाकर नहीं, उसके साथ संवाद करके दिया जाता है। इस दृष्टि से यह यात्रा संघ के लिए भी एक परीक्षा थी। भागवत ने विरोध का उत्तर आक्रामक भाषा में देने के बजाय एकात्मता, मानवता और सह-अस्तित्व की बात की। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। आलोचक उनके शब्दों और संघ के व्यवहार के बीच अंतर का प्रश्न उठा रहे है, समर्थक इसे संघ के मूल विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मान रहे हैं। इस बहस का अंतिम निर्णय समय और व्यवहार करेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि बहस अब अधिक प्रत्यक्ष और वैश्विक हो गई है।

मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को संघ की छवि पर वर्षों से चले आ रहे विवाद का अंतिम उत्तर मानना अतिशयोक्ति होगी। किंतु इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ अवश्य कहा जा सकता है। जिन लोगों ने संघ को केवल राजनीतिक आरोपों और विरोधी व्याख्याओं के माध्यम से जाना है, उन्हें पहली बार इतने बड़े वैश्विक मंच पर उसके शीर्ष नेतृत्व की विचार-दृष्टि को सीधे सुनने का अवसर मिला। यह यात्रा संघ के लिए एक उजाला इसलिए बनी है कि इसमें प्रतिरक्षा की भाषा कम और आत्मविश्वास की भाषा अधिक दिखाई दी। इसमें यह कहने का प्रयास था कि भारतीयता किसी के निषेध से नहीं, सबके सम्मान से मजबूत होती है, हिंदुत्व किसी समुदाय के बहिष्कार से नहीं, मानवता की एकात्म दृष्टि से सार्थक होता है और भारत की शक्ति उसकी समानता में नहीं, उसकी विविधताओं के बीच बनी रहने वाली सांस्कृतिक एकता में है।

आज विश्व को केवल आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसा जीवन-दर्शन भी चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके। भागवत के अमेरिकी संबोधन में भारत की इसी भूमिका की कल्पना दिखाई दी-एक ऐसा भारत जो अपनी परंपरा के बल पर विश्व को सह-अस्तित्व, संवाद और एकात्मता का रास्ता दिखा सके। मोहन भागवत की यह यात्रा इसलिए स्मरणीय रहेगी कि उसने संघ के बारे में चल रही बहस को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के सार्वजनिक विमर्श में पहुंचा दिया। अब संघ की पहचान केवल उसके विरोधियों के आरोपों या समर्थकों के दावों से नहीं, बल्कि उसके विचार, उसके व्यवहार और समाज के साथ उसके संवाद से तय होगी। अंततः किसी विचारधारा की सबसे बड़ी शक्ति उसका प्रचार नहीं, उसका आचरण होता है। अमेरिका की धरती से भागवत ने जो संदेश दिया है, उसकी वास्तविक कसौटी भारत की धरती पर सामाजिक समरसता, सेवा, संवाद और सह-अस्तित्व के रूप में दिखाई देगी। यदि यह संदेश व्यवहार में उतरता है, तो यह केवल संघ की छवि को नहीं, भारत की वैश्विक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई दे सकता है।

Mecca Defence Alliance की पहली बैठक में हुए बड़े फैसले, पाकिस्तान को मिली अहम जिम्मेदारी, भारत पर इसका क्या होगा असर?

नीरज कुमार दुबे

मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत गठित स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेटी की पहली बैठक ने पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के उभरते सुरक्षा समीकरण को नया और अधिक संगठित रूप दे दिया है। इस्तांबुल में हुई इस अहम बैठक में केवल रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात नहीं हुई, बल्कि 'मक्का डिफेंस अलायंस' को संस्थागत ढांचा देने, सऊदी अरब में स्थायी सचिवालय स्थापित करने और उसके शुरुआती तीन वर्षों के नेतृत्व की जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपने जैसे बड़े फैसले लिए गए। यही वह मोड़ है, जहां अब यह समझौता महज एक राजनीतिक घोषणा से आगे बढ़कर संभावित क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना का रूप लेता दिखाई दे रहा है।

हम आपको याद दिला दें कि 7 अगस्त को तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसकी तुलना नाटो के अनुच्छेद-5 जैसी सामूहिक रक्षा अवधारणा से की है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गठबंधन किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का स्थान भी नहीं लेगा।

बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह रही कि रियाद में मक्का डिफेंस अलायंस का स्थायी सचिवालय स्थापित किया जाएगा। इस सचिवालय का नेतृत्व महासचिव करेगा और शुरुआती तीन वर्षों के लिए पहला महासचिव पाकिस्तान से होगा। यह फैसला पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान के अनुसार, तीनों देशों ने गठबंधन के संस्थागत ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भविष्य में इसकी कार्यप्रणाली, बैठकों की व्यवस्था, राजनीतिक और सैन्य समन्वय तथा अन्य देशों की सदस्यता के नियमों पर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

हम आपको बता दें कि इस्तांबुल बैठक का एजेंडा बेहद व्यापक था। इसमें रक्षा क्षमताओं का विस्तार, तीनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी संचालनात्मक तालमेल, संयुक्त सैन्य उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी सहयोग, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण, खुफिया साझेदारी और आतंकवाद विरोधी सहयोग जैसे मुद्दे शामिल रहे। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुर्किये का रक्षा उद्योग तेजी से उभर रहा है, पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम देश होने के साथ रक्षा उत्पादन और सैन्य सहयोग का लंबा अनुभव रखता है, जबकि सऊदी अरब अपनी घरेलू रक्षा औद्योगिक क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश कर रहा है। यदि यह त्रिकोण संयुक्त अनुसंधान और उत्पादन तक पहुंचता है तो इसके परिणाम केवल सैन्य अभ्यासों तक सीमित नहीं रहेंगे।

देखा जाये तो यह बैठक ऐसे समय हुई जब पश्चिम एशिया और उसके आसपास का सुरक्षा वातावरण अत्यंत अस्थिर है। ईरान-अमेरिका तनाव, होरमुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा, लाल सागर में हूती हमले, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और गाजा शांति समझौते के दूसरे चरण से जुड़ी चुनौतियां भी चर्चा के प्रमुख विषयों में शामिल रहीं। हम आपको बता दें कि तुर्किये और पाकिस्तान को सऊदी अरब के नेतृत्व वाली लाल सागर सुरक्षा पहलों में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले देशों के रूप में देखा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि गठबंधन की सोच केवल सदस्य देशों की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि समुद्री सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय संकटों तक फैल सकती है।

साथ ही मक्का डिफेंस अलायंस के भविष्य का दूसरा बड़ा सवाल इसके विस्तार का है। फिलहाल मिस्र सबसे संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। मिस्र पहले से तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े आर-4 तंत्र का हिस्सा है और हाकान फिदान भी मिस्र की भागीदारी की इच्छा जता चुके हैं। बांग्लादेश का नाम भी संभावित भविष्य के संदर्भ में सामने आया है, हालांकि उसकी सदस्यता फिलहाल एजेंडे में नहीं दिखती। तुर्किये और पाकिस्तान सहित संस्थापक देशों की प्राथमिकता पहले तीन-सदस्यीय ढांचे को प्रभावी बनाना है। इसके बाद विस्तार का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

उधर, भारत के लिए इस घटनाक्रम को केवल एक और इस्लामी देशों के मंच के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब का रक्षा सहयोग यदि संस्थागत, तकनीकी और सैन्य स्तर पर गहरा होता है, तो यह दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच एक नए रणनीतिक संपर्क का निर्माण कर सकता है। भौगोलिकनक्शा खोजना

पहला महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की भूमिका है। सचिवालय के शुरुआती नेतृत्व और पहले महासचिव का पद पाकिस्तान को मिलने से उसे गठबंधन की संस्थागत दिशा तय करने में प्रभाव मिल सकता है। साथ ही, तुर्किये की उन्नत रक्षा तकनीक और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का संयोजन भविष्य में रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खोल सकता है। हालांकि भारत के लिए सबसे जटिल स्थिति तब बन सकती है, जब गठबंधन का विस्तार होगा। मिस्र भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, इसलिए काहिरा की संभावित सदस्यता नई दिल्ली के लिए विशेष ध्यान का विषय होगी। दूसरी ओर, यदि भविष्य में बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देश भी किसी व्यापक सुरक्षा ढांचे से जुड़ते हैं, तो क्षेत्रीय समीकरण और अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

बहरहाल, इस्तांबुल की पहली बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मक्का समझौता अब केवल हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं रहना चाहता। रियाद में सचिवालय, पाकिस्तान का प्रारंभिक नेतृत्व, संयुक्त रक्षा उत्पादन, सैन्य तालमेल और विस्तार की संभावना, ये सभी संकेत एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की ओर इशारा करते हैं। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि मक्का डिफेंस अलायंस नाटो जैसी प्रभावी सैन्य संरचना बन जाएगा क्योंकि इसके वास्तविक सैन्य दायित्व और संचालनात्मक व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब ने अब एक ऐसा संस्थागत मंच बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी दिशा और विस्तार आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र के रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

Created by Universal Document Converter

स्थायी करने की मांग पर अड़े अस्थायी सफाई कर्मचारी, कूड़े के ढेर में तब्दील कठुआ शहर, सरकार–प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

कठुआ 01 सितंबर। नगर परिषद कठुआ के अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को लगातार 15वें दिन भी जारी रही। सफाई कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उन्हें स्थायी करने को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वे हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। कर्मचारियों के आंदोलन के लंबा खिंचने के साथ ही अब कठुआ शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और शहर के कई हिस्से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके है।

कठुआ शहर के मुख्य मार्गों, चौक–चौराहों और बाजार क्षेत्रों में जगह–जगह कचरा और प्लास्टिक के लिफाफों के ढेर लगे हुए है। कालीबाड़ी से लेकर मुखर्जी चौक और हटली मोड़ तक कई स्थानों पर सड़कों के किनारे जमा कचरा अब सड़क तक फैल रहा है। लगातार हो रही बारिश ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बारिश के पानी के साथ कचरा सड़कों पर फैलने के साथ–साथ नालियों में जा रहा है जिससे कई जगह नालियां जाम होने की समस्या भी सामने आ रही है। कचरे के ढेरों से उठ रही दुर्गंध के कारण राहगीरा. ', दुकानदारों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर हालात ऐसे बन गए है कि लोगों को कचरे के ढेर के पास से गुजरना तक मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी अब उनके घरों और दुकानों तक पहुंच रही है। बारिश के कारण सड़कों पर फैला कचरा शहर की स्थिति को और बदहाल बना रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप होने के बावजूद जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से वैकल्पिक सफाई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यदि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है तो प्रशासन को शहर की सफाई व्यवस्था बनाए

रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रभावी कदम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर बैठकें और चर्चाएं तो हो रही है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा। शहर में जगह–जगह कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे है और आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर प्रशासन की यह निष्क्रियता गंभीर चिंता का विषय है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे इस बार आर–पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्थायी किए जाने का ठोस निर्णय होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे में अब सरकार और जिला प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, एक ओर कर्मचारियों की जायज मांग पर निर्णय लेना और दूसरी ओर शहर की सफाई व्यवस्था को तत्काल पटरी पर लाना।

शहरवासियों का कहना है कि यदि हालात इसी तरह बने रहे तो आने वाले दिनों में गंदगी और दुर्गंध की समस्या और गंभीर हो सकती है। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि सफाई कर्मचारियों की समस्या का जल्द समाधान किया जाए और जब तक हड़ताल समाप्त नहीं होती तब तक वैकल्पिक सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर शहरवासियों को गंदगी के बीच रहने से राहत दिलाई जाए। शहरवासियों का सीधा सवाल है कि जब कठुआ की सड़कों पर कचरा खुलेआम जमा है नालियां जाम हो रही हैं और लोग परेशान हैं, तो आखिर सरकार और प्रशासन की नजर इस गंभीर समस्या पर कब पड़ेगी?

हीरानगर में संदिग्ध कबूतर मिलने से मचा हड़कंप, पैरों में बंधी सामग्री ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता

हीरानगर, 01 सितंबर। सीमावर्ती क्षेत्र हीरानगर के शान खत्रियां गांव में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में

हलचल मच गई। स्थानीय स्तर पर कबूतर के पैरों में कुछ संदिग्ध सामग्री बंधी हुई पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शान खत्रियां गांव में लोगों की नजर एक कबूतर पर पड़ी जिसके पैरों में संदिग्ध सामग्री बंधी हुई थी। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही हीरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और कबूतर को बरामद कर लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के साथ–साथ संबंधित सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। कबूतर के पैरों में मिली सामग्री की जांच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसे कब और किस उद्देश्य से कबूतर के साथ बांधा गया था। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही है। कबूतर के संभावित मार्ग, बरामद सामग्री और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि फिलहाल बरामद सामग्री के संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कबूतर के पैरों में बंधी सामग्री का वास्तविक उद्देश्य क्या था और इसका सीमा क्षेत्र से कोई संबंध है या नहीं।

अमित कपूर ने कम स्टाइपेंड का विरोध करने वाले मेडिकल इंटर्न का किया समर्थन

सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की मांग की

जम्मू। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर ने जम्मू–कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न की हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। वे अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनके मासिक स्टाइपेंड को 12,300 रुपये मासिक से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए।

यहां जारी एक बयान में अमित कपूर ने उनका समर्थन किया। अमित कपूर ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए कहा है कि सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। विरोध कर रहे इंटर्न का कहना है कि कई बार अपील और विरोध–प्रदर्शन के बावजूद उनका स्टाइपेंड लगभग सात साल से नहीं बदला है जबकि दूसरे राज्यों में मेडिकल इंटर्न को इससे कहीं ज़्यादा पैसे मिलते है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा दिखाए गए तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में यह स्टाइपेंड बहुत कम है और इसे तत्काल से बढ़ाया जाना चाहिए। उनहोंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार ओडिशा 44,319

रुपये के मासिक स्टाइपेंड के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि पश्चिम बंगाल में मेडिकल इंटर्न को 43,099 रुपये और असम में 35,000 रुपये मिलते हैं।

उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से इसकी मांग कर रहे हें लेकिन लंबित मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद उन्हें काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमित कपूर ने कहा कि विरोध कर रहे एक इंटर्न की यह मांग बिल्कुल जायज है कि उन्हें उनके काम के घंटों के हिसाब से स्टाइपेंड मिले। उन्होंने कहा कि सात साल से उनका स्टाइपेंड लगभग 12,300 रुपये ही है। कई दूसरे राज्यों में इंटर्न को 25,000 से 45,000 रुपये के बीच स्टाइपेंड मिल रहा है। वे भी वही काम करते हैं, जिसमें 24 घंटे और रात की शिफ्ट और ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग शामिल है, लेकिन उनको रोज़ाना सिर्फ़ 400 रुपये के आसपास ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वह उनकी इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

चार साल से किराया दबाए बैठे दुकानदारों पर नगर परिषद की कार्रवाई, पुरानी सब्जी मंडी की दो दुकानें सील

कठुआ, 01 सितंबर। नगर परिषद कठुआ ने बकाया किराया जमा न करवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नगर परिषद की टीम ने पुरानी सब्जी मंडी में चार साल से किराया जमा नहीं करवाने वाली दो दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि अन्य दुकानदारा. ' ने भी यदि समय पर बकाया किराया जमा नहीं करवाया तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद कठुआ के सीईओ ने बताया कि पुरानी सब्जी मंडी में नगर परिषद की कई दुकानें लीज पर दी गई हैं। इनमें से कुछ दुकानदार पिछले करीब चार वर्षों से दुक. ानों का किराया जमा नहीं करवा रहे थे। नगर परिषद की ओर से संबंधित दुकानदारों को बकाया किराया जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे लेकिन

नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही बकाया राशि जमा करवाई गई। उन्होंने बताया कि इसी के चलते मंगलवार को हंसराज और रेनू बाला के नाम पर लीज पर दी गई दो दुकानों को सील कर दिया गया। दोनों दुकानों का पिछले चार वर्षों का करीब चार से पांच लाख रुपये किराया बकाया बताया गया है।

सीईओ ने कहा कि नगर परिषद की संपत्तियों का किराया समय पर जमा करवाना दुकानदारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर परिषद के अधीन आने वाली अन्य दुकानों में भी जिन दुकानदारों का किराया बकाया है उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि नोटिस के बावजूद बकाया किराया जमा नहीं करवाया गया तो संबंधित दुकानों को भी सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद किराया जमा न करवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ आगे लीज समाप्त कर दुकानों की पुनः नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। नगर परिषद ने सभी बकायेदार दुक. ानदारों को समय रहते अपना किराया जमा करवाने की चेता. वनी दी है, ताकि कड़ी कार्रवाई से बचा जा सके।

सामूहिक प्रयासों से ही बनेगा नशामुक्त समाज–डा. गुरु शर्मा

हीरानगर, 01 सितंबर। जिला उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा के दिशा–निर्देशों के तहत उप जिला अस्पताल हीरानगर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन निदेशक स्वास्थ्य विभाग जम्मू डा. पूनम सेठी के नेतृत्व तथा जिला चिकित्सा अधिकारी कठुआ डा. विजय रैना की निगरानी में किया जा रहा है।

इस दौरान ब्लॉक नोडल अधिकारी नशा मुक्त भारत अभियान डा. गुरु शर्मा ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा वर्करों को युवाओं में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रयासों से जम्मू–कश्मीर में नशे के खिलाफ अभियान को मजबूती मिली है। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर ही समाज को नशामुक्त बनाया जा सकता है। खंड चिकित्सा अधिकारी हीरानगर डा. रोमी शर्मा ने युवाओं को योग, खेलक. ूद एवं अन्य शारीरिक–मानसिक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर जिला हेल्थ ऑफिसर डा. उत्तम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर दविंदर सिंह सहित स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा वर्कर मौजूद रहे।

घुसपैठ ड्रोन और नशा तस्करी पर कड़ी नजर–एसएसपी मोहिता शर्मा ने मजबूत की सुरक्षा रणनीति

कठुआ, 01 सितंबर। जिले की आंतरिक सुरक्षा और कानून–व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा आईपीएस ने डीपीएल कठुआ के कॉन्फ्रेंस हॉल में आंतरिक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एसपी ऑप्स बॉर्डर, अतिरिक्त एसपी कठुआ, एसपी ऑप्स अपर कठुआ सहित सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी शामिल हुए।

बैठक में सीमा पर घुसपैठ के संभावित मार्गों, ड्रोन गतिविधियों, अंतरराज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था तथा पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई। अधिकारियों को नशा तस्करों, मवेशी तस्करों, ओजीडब्ल्यू, गैंगस्टरों, हिस्ट्रीशीटरों और अन्य संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा सूचनाओं का तत्काल आदान–प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

एसएसपी ने सीमा व अपर कठुआ में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग बढ़ाने, अंतरराज्यीय सीमाओं पर संयुक्त नाके लगाने और वाहनों की गहन जांच के निर्देश दिए। साथ ही गांव रक्षा गार्ड को मजबूत कर सुरक्षा ग्रिड और गश्त में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने पर जोर दिया। बैठक में लंबित मामलों की जांच निर्धारित 60/90 दिन की समयसीमा में पूरी करने तथा पुलिस रिकॉर्ड अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए। एसएसपी ने अधिकारियों से पेशेवर और जनहितैषी पुलिसिंग के साथ जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया।

जम्मू-कश्मीर में 136 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले, कठुआ में भी प्रशासनिक फेरबदल

कठुआ, 01 सितंबर। जम्मू–कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 136 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के तहत सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

आदेश के तहत कठुआ जिले में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अखिल सदोत्रा जेकेएएस जो कठुआ में प्रोजेक्ट ऑफिसर वेतन रोजगार के पद पर तैनात थे, का तबादला कर उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं गुलशन कुमार जेकेएएस को प्रोजेक्ट ऑफिसर वेतन–रोजगार एसीडी कठुआ के पद पर तैनाती दी गई है। इसके अलावा रमेश चंदर जेकेएएस जो खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे, का तबादला कर उन्हें उप निदेशक जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र कठुआ नियुक्त किया गया है। सरकार के आदेश में जम्मू–कश्मीर के विभिन्न विभागों और जिलों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आदेश के अनुसार संबंधित सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से तत्काल प्रभाव से रिलीव माना जाएगा ताकि वे नई तैनाती पर कार्यभार संभाल सकें।

सत्यमेव जयते
Government of Jammu and Kashmir

1975 के बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारत

जीडीपी के नए आंकड़ों के बीच चिदंबरम ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ के 7.8 प्रतिशत तक पहु. चने को लेकर जहां एक ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इन आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स का डाटा शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स से जुड़ी एक रिपोर्ट शेयर की। चिदंबरम द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 179 देशों की लिस्ट में 106वें स्थान पर है।श

चिदंबरम के मुताबिक, वी–डेम के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्कोर 1975 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने इस आंकड़े के साथ कोई अतिरिक्त टिप्पणी

नहीं की, लेकिन पोस्ट के जरिए भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए।

वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्दुनिया युद्ध में डूबी हुई है। चारों तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं। विश्व संकटों से घिरा हुआ है। सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नहीं नजर आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी ओर देश के भीतर भी निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गूंज और चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8 प्रतिशत ग्रोथ हासिल किया है।श

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमको इस गति को बनाए रखना है। हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र श्वोकल फॉर लोकलश, विदेशों की यात्राएं (घुमने–फिरने) नहीं करना चाहिए। विदेशों में शादी–ब्याह नहीं करना चाहिए। श्मेड इन इंडियाश के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे तो मुझे विश्वास है कि जब आजादी के 100 वर्ष होंगे तो हम युवा पीढ़ी को विकसित भारत सौंपेंगे।

वहीं जीडीपी के नए आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सोमवार को सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने देश की अर्थव्यवस्था की निराशाजनक तस्वीर पेश करते हुए इस वृद्धि पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तिमाही जीडीपी के आंकड़े, जिस तरह से रिपोर्ट किए गए हैं, अर्थव्यवस्था की एक अत्यंत विकृत तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये आंकड़े घरेलू और विदेशी दोनों ही क्षेत्रों में निजी निवेश की बेहद कमजोर भावना को नहीं दर्शाते हैं। कांग्रेस के संचार मामलों के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि उपभोक्ता विश्वास श्बेहद सुस्तश है। रमेश ने आरोप लगाया कि यह कोविड महामारी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और नवंबर 2025 से लगातार नीचे की ओर जा रहा है।

पल्ली मोड़ में दिनदहाड़े चोरी, अलमारी तोड़कर नकदी–जेवरात ले गए चोर, आंगन से स्कूटी भी उड़ाई

कठुआ, 01 सितंबर। जिला मुख्यालय कठुआ से करीब 10 किलोमीटर दूर पल्ली मोड़ क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी, जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं चोर घर के आंगन में खड़ी स्कूटी भी चोरी कर ले गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

पीड़ित गुरदीप सिंह ने बताया कि वह किसी जरूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे। करीब शाम पांच बजे जब वह वापस घर पहुंचे तो घर के अंदर रखी अलमारी टूटी हुई मिली। जांच करने पर अलमारी में रखी करीब 15 से 20 हजार रुपये की नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान गायब पाया गया। उन्होंने बताया कि उनकी माता की तबीयत खराब है और उनका विजयपुर स्थित एम्स में उपचार चल रहा है जिसके चलते वह घर से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर घर के आंगन में खड़ी स्कूटी नंबर जेके08पी–8678 भी ले गए। पीड़ित के अनुसार स्कूटी की चाबी घर के अंदर ही रखी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे है। पीड़ित गुरदीप सिंह ने आशंका जताई कि क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारण नशे के आदी युवाओं द्वारा ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि, पुलिस जांच के बाद ही चोरी के पीछे वास्तविक कारण और आरोपियों का पता चल सकेगा।

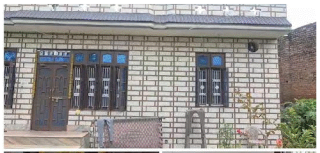

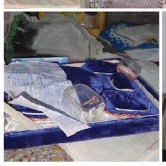

Created by Universal Document Converter

एससीओ समिट से भारत ने 13 अहम नतीजों पर दिया ज़ोर

सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सेंटर बनाना भी इनमें शामिल

बिश्केक। भारत ने आज शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट के कई अहम नतीजों पर ज़ोर दिया। इनमें सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मज़बूत करने और आतंकवाद व चरमपंथ जैसे अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के उपाय शामिल हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 13 नतीजों की सूची जारी की। इनमें से एक था एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए एक यूनिवर्सल सेंटर के नियमों को मंजूरी देना।

एमईए ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस सेंटर से एससीओ सदस्यों के बीच आतंकवाद, चरमपंथ, संगठित अपराध और अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने में सहयोग मज़बूत होने की उम्मीद है। साथ ही, इससे बेहतर तालमेल और जानकारी साझा करने में भी मदद मिलेगी।

सुरक्षा से जुड़ा यह फ़ैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य नेता मौजूद थे समूह से उन देशों का सामना करने का आह्वान किया जो आतंकवाद का इस्तेमाल सरकारी नीति के हथियार के तौर पर करते हैं।

प्रधानमंत्री ने एससीओ से आग्रह किया कि वे आतंकवादी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करें और आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में दोहरे मापदंडों को खारिज करें। इन बयानों को व्यापक रूप से पाकिस्तान पर सीधे हमले के तौर पर देखा गया।

मोदी ने कहा, हमें उन देशों को कड़ा संदेश देना चाहिए जो आतंकवाद का इस्तेमाल नीति के हथियार के तौर पर करते हैं और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह और समर्थन देते हैं, कि आतंकवाद कभी भी किसी के लिए रणनी. तिक संपत्ति नहीं हो सकता। एमईए द्वारा बताए गए नतीजों

में शबिश्केक घोषणापत्रश भी शामिल है। उम्मीद है कि इससे भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी पर अपना पक्ष रखने और मध्य एशिया व व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को मज़बूत करने का मंच मिलेगा।

एक और नतीजा एससीओ चार्टर में संशोधन और नई चीज़ें जोड़ने से जुड़ा प्रोटोकॉल है। इससे भारत को समूह के बदलते संस्थागत ढांचे को आकार देने में भाग लेने का मौका मिलता है और एससीओ ढांचे में अंग्रेज़ी को शामिल करने में मदद मिलती है। एससीओ एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा समूह है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने की थी। तब से इसका विस्तार हुआ है और इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं, जबकि कई अन्य देशों के पास ऑब्ज़र्वर या डायलॉग–पार्टनर का दर्जा है।

एससीओ का ढांचा मूल रूप से एक स्थायी यूरेशियाई अंतर–सरकारी और क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो सुरक्षा, आतंकवाद–रोधी उपायों और आर्थिक व राजनीतिक सहयोग पर केंद्रित है। इस ग्रुप ने इस साल अपनी 25वीं सालगिरह मनाई और किर्गिस्तान की अध्यक्षता में बिश्केक में समिट आयोजित की गई।

मंगलवार को विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एससीओ एंटी–नारकोटिक्स सेंटर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के नियमों को मंजूरी देने वाले फ़ैसले का भी ज़िक्र किया। इससे सदस्य देशों के बीच सीमा–पार नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को–टेररिज्म के ख़िलाफ़ बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। 13 नतीजा. ` में ड्रग की लत से निपटने और सिंथेटिक ड्रग्स व उनके प्रीकर्सर (कच्चे माल) के प्रसार को रोकने के लिए 2030 तक चलने वाले प्रोग्राम भी शामिल थे।

पहले प्रोग्राम का मकसद रोकथाम, इलाज और रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के क्षेत्र में बेहतरीन तरीकों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना है, जबकि दूसरे का मकसद एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने और ऑपरेशनल तालमेल को बेहतर बनाना है।

विदेश मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा प्रणालियों के विकास में सहयोग पर दिए गए बयानों का भी ज़िक्र किया। मंत्रालय ने कहा कि इनसे टेक्नोलॉजी, अनुभव और बेहतरीन तरीकों के आदान–प्रदान के साथ–साथ ऊर्जा प्रणालियों को आधुनिक बनाने और उन्हें मज़बूत करने में सहयोग की गुंजाइश बनती है। आपातक. ालीन स्थितियों से प्रभावित देशों को मदद देने के बारे में एससीओ के एक बयान पर भी ज़ोर दिया गया। इसमें कहा गया है कि यह आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा करने और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करता है।

एक और प्रोटोकॉल का मकसद अपराध से निपटने में एससीओ सरकारों के बीच सहयोग पर 2010 के समझौते में संशोधन करना है। इस संशोधन का मकसद संगठित और सीमा–पार अपराधों के ख़िलाफ़ कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल को मज़बूत करना है। विदेश मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का भी ज़िक्र किया, जो जलवायु अनुकूलन और शमन, जलवायु–लचीले विकास और टेक्नोलॉजी पर सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

एससीओ सदस्य देशों की अधिकृत एजेंसियों के बीच सूचना के क्षेत्र में सहयोग पर एक एमओयू भी नतीजों में शामिल था। इसका मकसद संस्थागत आदान–प्रदान को बढ़ावा देना और एससीओ सूचना क्षेत्र में भारत के नज़रिए और पहलों का व्यापक प्रसार करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में सहयोग पर एक एमओयू, विद. `श मंत्रालय द्वारा बताए गए नतीजों में आखिरी था। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत को अपना डिजिटल और एआई अनुभव साझा करने, एआई के ज़िम्मेदार और समावेशी इस्तेमाल को बढ़ावा देने और एससीओ के भीतर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप का विस्तार करने का मौका मिलता है।

तिरंगे का अपमान कर रहा था खालिस्तानी समर्थक सच्चे भारतीय ने लगाई फटकार तो बंद हो गया मुंह, किरेन रिजिजू बोले–सलाम है

नई दिल्ली। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे के दौरान खालिस्तान समर्थक द्वारा भारतीय ध्वज के अपमान के कई वीडियो सामने आए हैं। अब केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में तिरंगे का अपमान कर रहे शख्स को एक सच्चे भारतीय ने जमकर फटकार लगाई है। इस दौरान उस कथित खालिस्तानी समर्थक का मुंह एकदम बंद हो गया। वीडियो में वह न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी , पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थकों को भी खरी–खोटी सुनाता दिखाई देता है।

वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स ने ढोल बजाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान वहां खड़े अन्य लोग भारत समर्थन में आ गए और भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। वहीं तिरंगे के अपमान करने वाले शख्स को सच्चे भारतीय ने जमकर सबक सिखाया है। उन्होंने, न्यूयॉर्क के मेयर जो. हरान ममदानी और पाकिस्तान को भी खूब सुनाया।

वीडियो शेयर करते हुए रिजि. जू ने लिखा, शमैं इन सच्चे भारतीयों को सलाम करता हूं। उन नकली भारतीयों पर शर्म आती है, जो हमारे भरोसे को धोखा देते हैं और हमारे दुश्मनों के एजेंट के रूप में काम करते हैं। वे विदेशी धरती पर खुलेआम भारत को गाली देते हैं। वे जॉर्ज सोरोस और भारत विरोधी गिरोहों के सस्ते पेड एजेंट हैं।श

इससे पहले रिजिजू ने तिरंगे के कथित अपमान से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि सरकार को आरएसएस, बीजेपी या सरकार की आला. `चना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने लिखा था, शहम हमेशा कहते रहे हैं कि आपको आरएसएस, बीजेपी या सरकार की आलोचना करने की आजादी है, लेकिन हमारे राष्ट्र का अपमान मत करो। ध्यान से सुनें... हमारे झंडे और मेरे देश का अपमान मत करो। यह तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा।

कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में नहीं करेगी विरोध प्रदर्शन, वापस लिया फैसला; बताई वजह

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 5 सितंबर को अपने विरोध मार्च का आह्वान वापस ले लिया है। सीजेपी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह दिल्ली में 5 सितंबर को होने वाले विरोध मार्च के अपने आह्वान को वापस ले रही है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट को दिए गए उस आश्वासन के बाद लिया गया, जिसमें सरकार ने प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों को पूरा करने की बात कही है; इन वादों में 20 जुलाई को जंतर–मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में दर्ज एफआईआर को वापस लेना भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेपी के सौरव दास ने कहा, शमैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासनों और आज उन्हें मिली न्यायिक मान्यता को देखते हुए, और इस कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए, कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को होने वाले मार्च के आह्वान को वापस लेना उचित समझता है। उम्मीद है कि सरकार अपने वचन का पालन करेगी।

केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र, सीजेपी के नेताओं के साथ हुई बैठक में दिए गए तीनों आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला आश्वासन यह था कि केंद्र 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच दर्ज एफआईआर पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

दूसरा वादा यह दिया गया कि इस मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। तीसरा भरोसा यह था कि सरकार उन छात्रों के परिवारों को मुआवजा देगी जिन्होंने कथित तौर पर नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या की थी।

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, शकेंद्र सरकार नीट परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवज़ा देने के सीजेपी नेताओं से किए गए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है; हालांकि, इसके तौर–तरीके तय करने में 3 महीने का समय लगेगा।श उन्होंने आगे कहा, शफिलहाल, हम तीनों वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यह बात केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और अन्य राज्यों में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा के लिए छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने के एक दिन बाद सामने आई है।

गैलेक्सी बुक6 में एआई सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी और डिजाइन का नया अनुभव

मुम्बई। सैमसंग ने गैलेक्सी बुक6 को नए डिजाइन, बेहतर

कनेक्टिविटी और गैलेक्सी एआई सुविधाओं के साथ पेश किया है। कंपनी के अनुसार, नया लैपटॉप रोजमर्रा के काम को आसान बनाने और उपयोगकर्ताओं की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। गैलेक्सी बुक श्रृंखला में पहली बार इसे वायलेट सिल्वर रंग में उपलब्ध कराया गया है, जबकि ग्रे रंग का विकल्प भी दिया गया है।

गैलेक्सी बुक6 में 16:10 अनुपात वाला डिस्प्ले दिया गया है, जिससे दस्तावेज, वेब पेज और एक साथ कई कार्य करने के दौरान स्क्रीन पर अधिक ऊर्ध्वाधर जगह मिलती है। डिस्प्ले पर एंटी–रिफ्लेक्टिव परत दी गई है, जो अलग–अलग वातावरण में रोशनी के प्रतिबिंब को कम करने और देखने के अनुभव को अधिक आरामदायक बनाने में मदद करती है।

कनेक्टिविटी के लिहाज से लैपटॉप में 2 यूएसबी टाइप–सी पोर्ट दिए गए हैं और दोनों में समान क्षमताएं उपलब्ध हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को अलग–अलग पोर्ट की पहचान करने की परेशानी कम होती है। इसके अलावा यूएसबी टाइप–ए, एचडीएमआई 1.4 और 3.5 मिमी हेडफोन जैक भी मौजूद हैं। इन सुविधाओं के कारण बाहरी डिस्प्ले, उपकरण और अन्य सहायक सामग्री जोड़ने के लिए अतिरिक्त एडाप्टर पर निर्भरता कम होती है। सैमसंग ने गैलेक्सी बुक6 में गैलेक्सी एआई आधारित कई सुविधाएं भी जोड़ी हैं। एआई सिलेक्ट के जरिए स्क्रीन पर किसी सामग्री का चयन कर उससे जुड़ी जानक. ारी तेजी से हासिल की जा सकती है। एआई कट आउट तस्वीरों से पृष्ठभूमि हटाने में मदद करता है, जबकि नोट असिस्ट लंबे नोट्स का सार तैयार कर महत्वपूर्ण जानकारी को सामने लाता है।

गैलेक्सी उपकरणों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए क्विक शेयर, स्टोरेज शेयर और मल्टी कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। क्विक शेयर से फाइलें तेजी से साझा की जा सकती हैं। स्टोरेज शेयर के जरिए अनुकूल गैलेक्सी फोन और गैलेक्सी बुक उपकरणों में मौजूद तस्वीरों, वीडियो और फाइलों तक बिना पहले स्थानांतरित किए पहुंच बनाई जा सकती है। मल्टी कंट्रोल से एक ही कीबोर्ड और माउस के जरिए कई समर्थित उपकरण चलाए जा सकते हैं। सेकंड स्क्रीन सुविधा गैलेक्सी टैब को अतिरिक्त डिस्प्ले में बदल देती है। नियरबाय डिवाइसेज उपकरणों की खोज और कनेक्शन को आसान बनाता है, जबकि लिंक टू विंडोज के जरिए समर्थित फोन सुविधाओं. ` को कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सैमसंग ने बताया कि गैलेक्सी बुक6 को मजबूती और गुणवत्ता के लिए परीक्षणों से गुजारा गया है। सैमसंग केयर प्लस के तहत आकस्मिक नुकसान, मरम्मत और बदलने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

गैलेक्सी बुक6 चुनिंदा बाजारों में +799 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 8जीबी या 16जीबी मेमोरी तथा 256जीबी, 512जीबी और 1टीबी एसएसडी भंडारण विकल्प मिलते हैं। हालांकि, अलग–अलग क्षेत्रों में कीमत, उपलब्धता और तकनीकी विशेषताओं में बदलाव हो सकता है।

पाकिस्तान की अदालत ने मुस्लिम व्यक्ति से जबरन शादी के लिए ले जाई गई हिंदू लड़की को उसके माता–पिता को सौंपा

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक हिंदू लड़की को उसके माता–पिता को सौंप दिया। आरोप था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसे बहला–फुसलाकर रिश्ते में फंसाया और फिर इस्लाम अपनाने और उससे शादी करने के लिए मजबूर किया।

सिंध के संघार ज़िले की खिपरो तहसील की राणा राजपूत कॉलोनी की रहने वाली 21 साल की रीता पिछले हफ़्ते अपने घर से लापता हो गई थीं। उनके भाई रवि शंकर ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी।

शंकर का आरोप था कि परिवार के घर के सीसीटीवी फुटेज में कुछ अनजान लोग 24 अगस्त को उनकी बहन को कीमती सामान और मोबाइल फ़ोन के साथ ले जाते हुए दिखे थे।

शिकायत के मुताबिक, रीता को कथित तौर पर लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर पंजाब के गुजरांवाला ले जाया गया, जहाँ उन पर इस्लाम अपनाने और पहले से शादीशुदा नज़ीर हुसैन से शादी करने के लिए दबाव डाला गया।

बाद में पंजाब पुलिस ने रीता को बरामद किया और सोमवार को उन्हें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत से रीता को सरक. ारी शेल्टर होम शदारुल अमानश भेजने का अनुरोध किया। अधिकारी का दावा था कि रीता अपने माता–पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती थीं।

अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया, ष्हालांकि, उनके वकीलों असद जमाल और खेता राम ने इस अनुरोध का विरोध किया और अदालत को बताया कि रीता अपने भाई के साथ घर लौटना चाहती हैं, जो अदालत में मौजूद थे। मजिस्ट्रेट ने रीता से शपथ लेकर अपना बयान दर्ज करने को कहा।

उन्होंने बताया, ष्अपने बयान में रीता ने कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से अपने माता–पिता के घर लौटना चाहती हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें अपने भाई के साथ जाने की इजाज़त दे दी और भाई को उनकी सुरक्षा और संघार में परिवार के घर तक सुरक्षित पहुँचाने की ज़िम्मेदारी सौंपी।

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुमानों के मुता. बिक, पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों अल्पसंख्यक लड़कियों को ज़बरदस्ती, अपहरण या धर्म परिवर्तन और शादी के दबाव का शिकार बनाया जाता है।

अधिकार समूहों का दावा है कि पीड़ितों में एक बड़ा हिस्सा हिंदू समुदाय से होता है और कई मामलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले परिवारों की लड़कियां शामिल होती हैं। उन्होंने कमज़ोर अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मज़बूत कानूनी सुरक्षा उपायों और ज़्यादा असरदार जांच की बार–बार मांग की है।

बदला लेने की सोचना भी मत...पहले ईरान पर मिसाइल बरसाया, फिर इस अंदाज में ट्रंप ने धमकाया

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर हमले कर रही है, और साथ ही उन्होंने तेहरान को जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इन अमे. रिकी हमलों को पूरीतरह से जायज बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने के विफल प्रयास और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागने के जवाब में की गई है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान अमेरिकी हमलों का कोई जवाब देता है, तो उस पर ष्कहीं अधिक कड़ा और बड़े स्तर का हमलाष् किया जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी होर्मुज जलडमरूमध्य के पास

ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं। ये हमले ईरानियों की उन नाकाम को. शिशों के जवाब में हैं जिनमें उन्होंने जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की को. शिश की थी, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है! और जॉर्डन में हमारे सैन्य अड्डे पर आठ मिसा. इलें दागी थीं, जिन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया।

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जो एक नाकाम देश है – इस पूरी तरह से जायज हमले का जवाब देता है, तो उस पर बहुत ज्यादा और बड़े स्तर पर फिर से हमला किया जाएगा, लेकिन यह उन सभी हमलों में सबसे बड़ा हमला नहीं होगाय वह हमला अभी बाकी है और जब वह होगा, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बहुत कम हिस्सा ही बचेगा। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर नए हमले किए। यह दो दिनों में दूसरा हमला था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो और भी ज्यादा विनाशकारी हमला किया जाएगा।

नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,000 के करीब पहुंची, और शव बरामद हुए

काठमांडू। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई, क्योंकि सुरक्षा बलों ने देश के अलग–अलग हिस्सों से और शव बरामद किए।

अधिकारियों का अनुमान है कि 3,916 लोग (जिनमें 583 विदेशी भी शामिल हैं) अभी भी लापता हैं, जबकि नेपाल सेना सहित सुरक्षाकर्मी प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान तेज कर रहे हैं।

नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, चितवन से 321, नवलपरासी ईस्ट से 216, नवलपरासी वेस्ट से 170 और नुवाकोट से 95 शव बरामद किए गए।

इसी तरह, गोरखा से 65, धाडिंग से 55, तनहुन से 38 और रसुवा से 27 शव बरामद किए गए।

एनडीआरआरएमए ने बताया कि अचानक आई इस बाढ़ से आठ जिले प्रभावित हुए हैं। साथ ही बताया कि घायल हुए 279 लोगों में से 168 को इलाज के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

Created by Universal Document Converter

वेदांता प्रस्तुत करता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल: किताबों, विचारों और संवाद के जरिए भारत की सोच को नया आकार देने के 20 सालों का जश्न

राजस्थान सरकार के निरंतर सहयोग से, ऐतिहासिक 20वां संस्करण साहित्यिक–सांस्कृतिक आदान–प्रदान और अनेक भाषाओं में संवाद की ताकत के दो दशकों का उत्सव मना रहा है

जम्मु/कश्मीर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जनवरी 2027 में अपने ऐतिहासिक 20वें संस्करण के आयोजन की तैयारी कर रहा है। फेस्टिवल अपने उन दो दशकों का जश्न मना रहा है जिनमें वह लेखकों, विचारकों, कलाकारों और दर्शकों के साथ उन किताबों को एक मंच पर लेकर आया जिन्होंने हमें दुनिया को समझने में मदद की है।

बीते दो दशकों में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर में लेखकों और पाठकों के एक सालाना सम्मेलन से कहीं बढ़कर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक मंचों में से एक बन गया है, जिसने भारत और विश्वभर के दर्शकों के साहित्यिक आयोजन के अनुभव और चर्चाओं तक पहुँचने के तरीके को बदल दिया है।

2006 में अपनी स्थापना के बाद से, फेस्टिवल ने 8,000 से अधिक लेखकों, वक्ताओं और कलाकारों की मेजबानी की है, 50 लाख से अधिक दर्शकों का स्वागत किया है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रसारण सहयोगियों और मीडिया नेटवर्क के माध्यम से अनुमानित 1 अरब से अधिक दर्शकों तक अपनी पहुँच बनाई है।

अपने इस विस्तार के साथ अलावा, फेस्टिवल का सबसे जरूरी प्रभाव साहित्य और विचारों को आम बातचीत के केन्द्र में लाने की क्षमता है। फेस्टिवल विविध आवाजों के लिए एक स्वतंत्र और सहज मंच बनकर उभरा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने साहित्यिक जुड़ाव को पारंपरिक प्रकाशन और शैक्षणिक दायरों से आगे ले जाने में भी मदद की है, जिससे किताबें, विचार और बौद्धिक संवाद दर्शकों की एक बड़ी संख्या के बीच आसानी से पहुँचे।

बीस वर्षों में, फेस्टिवल ने भारत के समकालीन साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह फेस्टिवल एक ऐसा साझा स्थान बन गया जहाँ साहित्य, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, दर्शन, कला और समकालीन संस्कृति के बीच संवाद की अविरल धारा बहती है। जयपुर से लेकर पूरी दुनिया तक, फेस्टिवल का विस्तार एक अंतरराष्ट्रीय परिघटना की तरह हुआ है, इस सूची में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व, मालदीव और आयरलैंड जैसे देशों के 15 से अधिक संस्करण शामिल हैं। इन संस्करणों के माध्यम से, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु बनकर उभरा है, जो भारत की साहित्यिक परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से जोड़ता है, साथ ही वैश्विक संवादों को भारतीय दृष्टि के साथ संवाद में लाता है। हालांकि यह भी सच है कि आज फेस्टिवल का प्रभाव अपने आयोजित संस्करणों से कहीं निकल चुका है, भारत और दुनियाभर में 300 से अधिक साहित्यिक आयोजन और फेस्टिवल उस खुले साहित्यिक आदान–प्रदान की संस्कृति से प्रेरणा लेते हैं जिसको विकसित करने में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का बड़ा योगदान है। इसके अलावा, यह मंच साहित्यिक आयोजनों की उस बढ़ती भूमिका को भी दिखाते हैं जो लेखकों, पाठकों और विचारों को दर्शकों की एक बड़ी संख्या के बीच लेकर जाती है।

इस दौरान, फेस्टिवल ने साहित्य, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन की कुछ सबसे प्रभावशाली आवाजों की मेजबानी की है, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता, राष्ट्राध्यक्ष, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, कलाकार और वैश्विक विचारक शामिल हैं।

फेस्टिवल की यह शानदार यात्रा राजस्थान सरकार के लगातार साथ देने से मुमकिन हुई है। 2008 में फेस्टिवल शुरू होने से लेकर आज तक सरकार का यह साथ इसके विकास और पहचान का अहम हिस्सा रहा है। राजस्थान ने फेस्टिवल को एक खास जगह और शानदार सांस्कृतिक माहौल दिया है। इसी लगातार साथ और राज्य के संसाधनों की मदद से यह फेस्टिवल सिर्फ लेखकों और पाठकों की एक सभा से आगे बढ़कर दुनिया भर में मशहूर साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच बन गया है। बदले में, इस फेस्टिवल ने जयपुर और राजस्थान को दुनिया भर के साहित्यिक जगत में मजबूत पहचान दिलाई है। यहाँ भारत और दुनिया भर से मशहूर लेखक, विचारक और कलाकार आते हैं, दर्शक आते हैं और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जाता है।

स्वतंत्र विचार, सहजता और समावेशिता फेस्टिवल की इस यात्रा के आधार–स्तंभ रहे हैं। एक ऐसे समय में जब साहित्यिक संवाद अक्सर साहित्यिक गलियारों तक सीमित रह जाते थे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने पढ़ने, सुनने और वैचारिक आदान–प्रदान की सहभागी संस्कृति बनाने की कोशिश की और पीढ़ियों, भाषाओं, विषयों और भौगोलिक सीमाओं के पार की आवाजों को एक मंच पर लाने का काम किया।

यह यात्रा अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति एक निरंतर प्रतिबद्धता से भी पहचानी जाती रही है। इन दो दशकों में, फेस्टिवल ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की आवाजों को बढ़ावा दिया है, अनुवाद संस्कृति को मजबूत किया है, अलग–अलग भाषाओं के बीच बातचीत के अवसर बनाए हैं।

बहुभाषी कार्यक्रमों,

अनुवाद–सत्रों, और भारतीय व अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के लेखकों के माध्यम से, फेस्टिवल ने क्षेत्रीय आवाजों और साहित्यिक परंपराओं को एक बड़े दर्शक–समूह तक पहुँचाने के रास्ते बनाए हैं, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि हर भाषा में ऐसी कहानियाँ, इतिहास और आयाम होते हैं जो व्यापक सांस्कृतिक संवाद को समृद्ध करते हैं। अपनी 20वीं वर्षगांठ के इस पड़ाव के हिस्से के रूप में, फेस्टिवल की यह घोषणा भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में एक साथ जारी की गई है, जो भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं के पार विविध दर्शकों तक विचारों और कहानियों को पहुँचाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

फेस्टिवल का कार्यक्रम इस विश्वास को दर्शाता है कि ज्ञान परस्पर जुड़ा हुआ है। फेस्टिवल साहित्य, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, लैंगिक अध्ययन, स्वास्थ्य, प्रवासन और पर्यावरण से जुड़े संवादों को एक साथ लाता है।

विचारों, कहानियों और संवाद के 20 सालष की थीम पर आधारित, 20वां संस्करण निरंतरता और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करता है। अपनी विरासत का उत्सव मनाते हुए, फेस्टिवल एक साझा दुनिया में साहित्यिक संस्कृति के भविष्य की ओर भी देखता है।

टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता संजॉय के. रॉय ने कहारू ष्बीस वर्षों से, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इस सहज विश्वास पर कायम रहा है कि किताबों और विचारों में लोगों को साथ लाने की शक्ति होती है। हमारे लेखकों की उदारता, हमारे दर्शकों की जिज्ञासा, और भाषाओं, संस्कृतियों व दृष्टिकोणों के पार संवाद के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता ने इस फेस्टिवल को इतना सफल बनाया है। अपने बीसवें संस्करण में प्रवेश करते समय, हम इस यात्रा का उत्सव मनाते हुए, आगे आने वाले अनगिनत संवादों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।ष

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह–निदेशक नमिता गोखले ने कहारू ष्भारत की आत्मा उसकी साहित्यिक विरासत और भाषाई विविधता में बसती है। यह उचित ही है कि हम अपनी भाषा स्वरमाला शृंखला के माध्यम से अनेक भाषाओं को याद करते देते हुए अपने ऐतिहासिक 20वें साल का उत्सव मना रहे हैं।ष

टीमवर्क आर्ट्स की प्रमुख प्रीता सिंह ने कहारू ष्बीते दो दशकों में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दुनिया के अग्रणी साहित्यिक और सांस्कृतिक मंचों में से एक बनकर उभरा है। फेस्टिवल किताबों, विचारों और सार्थक संवाद की शक्ति में अपने भरोसे के साथ खड़ा रहा है। यह यात्रा न केवल असाधारण लेखकों और दर्शकों से संभव हुई है, बल्कि हमारे उन साझेदारों, प्रायोजकों और संस्थानों के सहयोग से भी संभव हुई है जो संस्कृति की परिवर्तनकारी भूमिका में हमारे विश्वास के साझीदार हैं। इस ऐतिहासिक 20वें संस्करण का उत्सव मनाते हुए, हम फेस्टिवल के अगले संस्करण की ओर भी देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य साझा सहयोग, नए दर्शकों तक पहुँचने के साथ ही भारत और दुनियाभर में एक सहज सांस्कृतिक हस्तक्षेप करना है। हमारा दृष्टिकोण उन साझेदारियों को बढ़ावा देना है जो साहित्य, विचारों और सार्वजनिक विमर्श का समर्थन करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फेस्टिवल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्र, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रासंगिक मंच बना रहे।ष

राजस्थान सरकार के सहयोग से, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 20वां संस्करण 14 से 18 जनवरी 2027 तक जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और कला की अग्रणी आवाजें एक साथ आएँगी।

अपने तीसरे दशक में प्रवेश करते हुए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अपनी अनूठी विरासत को सहेजना जारी रखेगा, ताकि पीढ़ियों, भाषाओं और भौगोलिक सीमाओं के पार दर्शकों के लिए साहित्य और विचारों को और सुलभ, सहभागी और प्रासंगिक बनाया जा सके। फेस्टिवल ऐसे मौके और स्थान निर्मित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा जहाँ विविध आवाजें संवाद का हिस्सा बनकर विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रेरित करती हैं।

2006 में स्थापित, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को दुनिया के अग्रणी साहित्यिक आयोजनों में से एक और साहित्य, विचारों तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान के एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है।

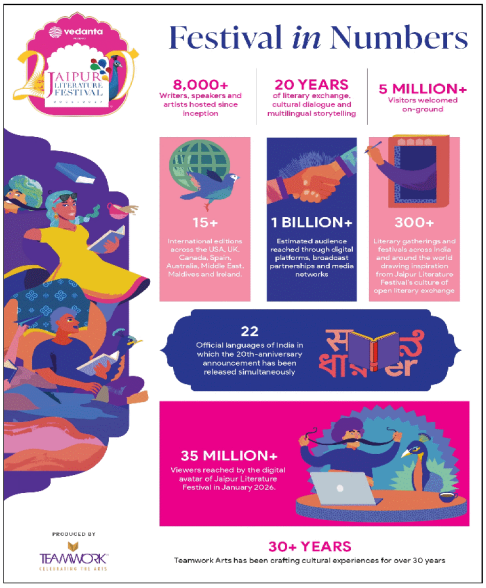

एससीऔ के मंच से चीन और पाकिस्तान को एक साथ धोकर मोदी ने दुनिया की वाहवाही लूट ली

नीरज कुमार दुबे

एससीओ शिखर सम्मेलन में वैसे तो सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने संबोधन में तमाम तरह के मुद्दे उठाये लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में शामिल मुद्दों की विविधता और सबको साथ लेकर चलने के जज्बे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साथ ही तमाम अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक भी यह देखकर हैरान हैं कि कैसे मोदी ने मंच पर साथ मौजूद चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया तो वहीं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सवाल पर चीन को भी आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद पर मोदी ने दो टूक कहा कि जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं और आतंकवाद को अपनी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंक कभी किसी की रणनीतिक संपत्ति नहीं बन सकता। वहीं कनेक्टिविटी के नाम पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौते को अस्वीकार करते हुए उन्होंने चीन को भी साफ संदेश दिया।

किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी मौजूदगी को महज औपचारिक भागीदारी तक सीमित नहीं रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के 25 वर्षों की यात्रा को अगले 25 वर्षों की दिशा तय करने के अवसर में बदलते हुए भारत का स्पष्ट एजेंडा सामने रखा। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्च्युनिटी के जरिये मोदी का संदेश था कि अब केवल घोषणाओं और संवाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना होगा। इतिहास

प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे धारदार हिस्सा आतंकवाद पर था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ कार्रवाई केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आतंकवादी वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ, सुरक्षित ठिकानों और पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड को स्वीकार करने से साफ इंकार किया। यह संदेश ऐसे मंच से आया, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्वयं मौजूद थे।

भारत की कूटनीतिक उपलब्धि यहीं समाप्त नहीं हुई। एससीओ के 25 वर्ष पूरे होने पर स्वीकार की गई बिश्केक डिक्लेरेशन ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती दी। घोषणा और शिखर सम्मेलन के अन्य फैसलों में आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुरक्षा चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए यूनिवर्सल

सेंटर संबंधी नियमों को मंजूरी देना सदस्य देशों के बीच समन्वय और सूचना आदान–प्रदान को मजबूत करने वाला कदम है।

भारत के लिए विशेष महत्व की बात यह भी रही कि अंग्रेजी को एससीओ के संस्थागत ढांचे में शामिल करने की दिशा में प्रगति हुई। साथ ही भारत द्वारा आगे बढ़ाई गई कई पहलों जैसे– एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, यंग साइंटिस्ट फोरम और यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव को भी बिश्केक डिक्लेरेशन में स्थान मिला। यह संकेत है कि भारत अब एससीओ में केवल सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठाने वाला देश नहीं, बल्कि संगठन के बौद्धिक, सांस्कृतिक और संस्थागत भविष्य को आकार देने वाला सक्रिय साझेदार बन रहा है।

मोदी ने अपनी विदेश नीति की व्यापक सोच को भी भाषण में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यूरेशिया की सुरक्षा और शांति का संबंध अफगानिस्तान की स्थिरता से जुड़ा है और भारत वहां विकास तथा मानवीय सहायता जारी रखेगा। पश्चिम एशिया के संघर्षों का उदाहरण देते हुए उन्होंने आगाह किया कि आज की दुनिया में किसी एक क्षेत्र का युद्ध उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उसका असर ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है, जिसका सबसे अधिक बोझ ग्लोबल साउथ को उठाना पड़ता है। इसलिए भारत का स्पष्ट मत है कि युद्धों और तनावों का समाधान रणभूमि पर नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। सरकारीएजेंसियां

प्रधानमंत्री ने नशे के कारोबार को भी क्षेत्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी केवल अपराध नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय स्थिरता पर हमला है। इस संदर्भ में एससीओ के तहत सुरक्षा, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और नारकोटिक्स से निपटने के लिए बनाए जा रहे केंद्रों को प्रभावी और त्वरित कार्रवाई का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। इस तरह आतंकवाद और नार्को–टेररिज्म के खिलाफ भारत की चिंता को व्यापक एससीओ एजेंडे से जोड़ने में सफलता मिली।

कनेक्टिविटी पर भी मोदी का संदेश उतना ही स्पष्ट और कूटनीतिक रूप से अहम था। भारत बाजारों को जोड़ने, व्यापार बढ़ाने और विकास के नए रास्ते खोलने वाली सभी पहल का समर्थन करता है, लेकिन ऐसी किसी भी परियोजना के लिए सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। प्रधानमंत्री का यह संदेश चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल और विशेष रूप से चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है। भारत लंबे समय से इस परियोजना का विरोध करता रहा है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। ऐसे में मोदी ने बिना किसी देश या परियोजना का नाम लिए एससीओ मंच से साफ कर दिया कि कनेक्टिविटी और विकास के नाम पर किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने सड़क, रेल और हवाई संपर्क बढ़ाने के अलावा कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

तीसरे स्तंभ यानि अपॉर्च्युनिटी के जरिए मोदी ने एससीओ सहयोग को आम लोगों से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि युवाओं के लिए कितने अवसर बने, उद्यमियों के लिए कितने नए बाजार खुले, किसानों को तकनीक से कितना लाभ मिला और नागरिकों का जीवन कितना बेहतर हुआ। मोदी ने जोर दिया कि एससीओ सहयोग केवल सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि पीपुल–ड्रिवन पार्टनरशिप बनना चाहिए। इसी दिशा में भारत इस वर्ष पहले एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम की मेजबानी करेगा।

इसके अलावा, शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातों ने भी भारत की सक्रिय कूटनीति को मजबूत किया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, जबकि लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसौलिथ के साथ द्विपक्षीय संबंधों और संपर्क को मजबूत करने पर बातचीत हुई। ये मुलाकातें बताती हैं कि बहुपक्षीय मंचों पर भारत की रणनीति केवल भाषण देने की नहीं, बल्कि समानांतर रूप से द्विपक्षीय संबंधों का नेटवर्क मजबूत करने की भी है। इतिहास

बहरहाल, बिश्केक एससीओ समिट में मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, दोहरे मापदंडों को चुनौती दी, संप्रभुता आधारित कनेक्टिविटी का सिद्धांत दोहराया और भारत की सांस्कृतिक व युवा–केंद्रित पहलों को एससीओ के एजेंडे में स्थापित किया। उनका संदेश साफ था कि "शेयर्ड जियोग्राफी" को "शेयर्ड अपॉर्च्युनिटीज" में बदलना होगा, विजन को परिणामों में और सरकार–केंद्रित सहयोग को जन–केंद्रित साझेदारी में परिवर्तित करना होगा। कुल मिलाकर, बिश्केक से भारत ने यही संकेत दिया है कि बदलते यूरेशियाई समीकरणों में वह एजेंडा तय करने वाला देश बन चुका है।

Created by Universal Document Converter

पावरग्रिड की 37वीं वार्षिक आम बैठक सम्पन्न

लद्दाख टुडे संवाददाता

गुरुग्राम। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन महारत्न सीपीएसयू की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन दिनांक 20 अगस्त, 2026 को वर्चुअल माध्यम से किया गया।

इस वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता श्री वम्सी राम मोहन बुर्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ने की। इस अवसर पर डॉ. यतींद्र द्विवेदी, निदेशक (कार्मिक), श्री नवीन श्रीवास्तव, निदेशक (प्रचालन), श्री अमोल टावरी, निदेशक (वित्त), श्री अभय बाकरे, सरकार द्वारा नामित निदेशक,तथा वर्चुअल माध्यम से शेयरधारक उपस्थित रहे।

एजीएम के दौरान कंपनी की प्रमुख वित्तीय उपलब्धियां, परिचालन संबंधी सफलताएं, भावी विकास योजनाएं, तकनीकी नवाचार और पहलें प्रस्तुत की गईं तथा शेयरधारक.ों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया गया। शेयरधारकों ने कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की एवं कंपनी के निरंतर विकास के लिए शुभकामनाएं दीं।

दिनांक 31 जुलाई 2026 तक पावरग्रिड 292 सब–स्टेशनों, 1,86,889 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों और 6,37,016 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को कमीशन कर संचालित कर रहा है। नवीनतम उपकरणों और तकनीकों को अपनाने, स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उन्नत उपयोग से, पावरग्रिड 99.81: की औसत ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता बनाए रखने में सक्षम रहा है।

एनएच-44 पर जिंदगी से खिलवाड़! जतवाल में ओवरलोड ऑटो बना हादसे का न्योता

छत पर बैठे स्कूली बच्चे और पीछे लटककर सफर–अगर हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन?

घगवाल (निखिल पंगोत्रा)। राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। घगवाल के अधीन जतवाल क्षेत्र में एक पैसेंजर ऑटो क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ता नजर आया। हैरानी की बात यह है कि ऑटो में स्कूली बच्चों को भी बेहद जोखिम भरे तरीके से बैठाया गया था। कुछ बच्चे छत पर बैठे नजर आए तो कुछ पीछे लटककर सफर करते दिखाई दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चलते समय इस जर्जर हालत के ऑटो का टायर फट जाए, चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ जाए या अचानक कोई हादसा हो जाए तो इन बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?

क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? जतवाल में यातायात विभाग के

डीएसपी का नाका भी लगाए जाने की बात सामने आती है। इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर इस तरह ओवरलोड वाहन बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि अगर नाके के बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है तो निगरानी और कार्रवाई व्यवस्था पर सवाल क्यों न उठें? एक तरफ प्रशासन और यातायात विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क पर क्षमता से अधिक सवारियां लेकर चलने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। स्कूली बच्चों को छत पर बैठाकर और वाहन के पीछे लटकाकर सफर करवाना महज यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। यदि समय रहते ऐसे वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई तो किसी दिन छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना का कारण बन सकती है। अब देखना यह है कि संबंधित यातायात विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या फिर ऐसे वाहन इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर नियमों को चुनौती देते हुए दौड़ते रहेंगे। सवाल सीधा है‌ नाका मौजूद है, नियम मौजूद हैं, जिम्मेदार विभाग मौजूद है, फिर भी ओवरलोड ऑटो सड़क पर बेखौफ क्यों? आखिर जिम्मेदार कौन?

पुराना पिंड पुल को चौड़ा करने के लिए राशि मंजूर होने पर विधायक का किया गया धन्यवाद

आरएस पुरा। शिव नगर चौक से पुराना पिंड की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर बने पुल को चौड़ा करने के

लिए विधायक द्वारा राशि मंजूर किए जाने का सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र सूदन ने विधायक तथा संबंधित विभाग का धन्यवाद किया है और कहा है कि लोगों की विधायक ने एक पुरानी मांग पूरी की है। उनका कहना है कि इस मांग को लेकर स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए गए और चुनाव के समय विधायक की तरफ से लोगों के साथ वादा किया गया था कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा और अब उन्हें जानकारी मिली है कि विधायक के प्रयासों के कारण पुल को चौड़ा करने के लिए राशि मंजूर हो चुकी है और जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर बने पुल की चौड़ाई कम होने के कारण हर समय जहां पर जाम जैसी स्थिति बनी रहती थी और खासकर विद्यार्थियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती लोग भी इसी पुल का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं ऐसे में पुल के चौड़ा होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों के कारण क्षेत्र में काफी विकास कार्य हो रहे हैं और अब उनकी तरफ से लोगों की पुरानी एवं जायज मांग को पूरा किया गया है। इस मौके पर उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे।

बटवाल सुधार सभा का चेयरमैन बनने पर सतपाल मांडी को किया गया सम्मानित

आरएस पुरा। बटवाल सुधार सभा का चेयरमैन बनने पर मंगलवार को स्थानीय लोगों की

तरफ से सतपाल मांडी को गांव चक सियां के लोगों द्वारा सम्मानित किया गया तथा उन्हें सभा में नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर गांव के नंबरदार महेंद्रजीत सिंह, अमरजीत सिंह, अमरनाथ लोरिया, सदरी लाल भगत तथा हरबंस लाल अंग.ुराना सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे जिन्होंने सतपाल मांडी को हार पहना कर सम्मानित किया तथा उन्हें बटवाल सुधार सभा का चेयरमैन बनाए जाने पर मुबा.रकबाद दी और उनके द्वारा समाज की बेहतरी हेतु लगातार किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की। इस मौके पर नंबरदार महेंद्रजीत सिंह ने कहा कि सतपाल मांडी पिछले लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहे हैं और हमेशा ही लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाते रहते हैं और उनके बेहतर कार्यों को देखते हुए बटवाल सुधार सभा का चेयरमैन बनाया गया है जिसके चलते उन्हें आज सम्मानित किया गया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह आगे भी समाज की भलाई तथा समाज को एकजुट करने के लिए कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर पूर्व पंच सत्या देवी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

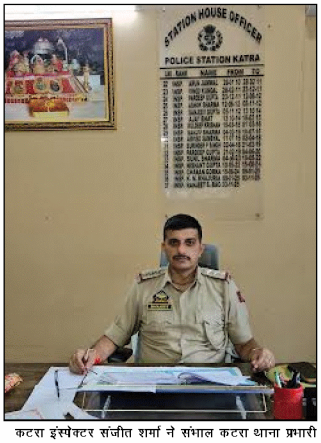

कटरा इंस्पेक्टर संजीत शर्मा ने संभाल कटरा थाना प्रभारी का पदभार।

छाया: रोहित शर्मा।

Printer, Publisher, Owner, Editor by: Sanktha Prasad Singh Published from: GH Road Skara, Near Ladakh Public School, Leh (Ladakh) - 194104, Published from: Ladakh Imperial Printing press, Gh Skara, Near Ladakh Public School, Leh Ladakh, 194104, Mob.: Mob.: 9818069272, 8287390112, Email: ladakhtoday@gmail.com
**All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Leh - city.

Created by Universal Document Converter